RNI No. DELMUL/2012/47011

01 जुलाई, 2026 मंगलवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 91

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

महिला क्रिकेट को सभी विभागों में सुधार करना होगा : मजूमदार 07

संक्षिप्त वार्ता

अमेरिका के जंगल में लगी आग से जूझते हुए तीन वाइल्डलैंड फायर फाइटर्स की मौत

वेब वार्ता,न्यूयार्क। अमेरिकी वाइल्डलैंड फायर सर्विस ने बताया कि शनिवार को कोलोराडो-यूटा सीमा पर तेजी से फैल रही जंगल की आग से जूझते हुए तीन वाइल्डलैंड फायर फाइटर्स की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से झुलस गए। अधिकारियों के मुताबिक भीषण गर्मी, शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है। इन परिस्थितियों के चलते देशभर में बेकाबू बड़ी जंगल की आग की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। कोलोराडो के मेसा काउंटी में नोल्स और गोर में लगी आग पर काबू पाने के दौरान फायरफाइटर्स पर आग की बढ़ती लपटों का हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी गृह विभाग ने इसे बर्नओवर घटना बताया, जिसमें क्रू ने इमरजेंसी फायर शेल्टर तैनात किए। बताया जा रहा है कि बचे हुए दो फायरफाइटर्स को जलने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह विभाग ने कहा कि नोल्स और गोर की आग बाद में दूसरी आग के साथ मिलकर स्नाइडर फायर बन गई।

आर्टिगा ट्रक से टकराई महिला समेत 5 घायल

वेब वार्ता, अलीगढ़। थाना महुआखेड़ा क्षेत्र में हवाई पट्टी के सामने फरुर्खाबाद से दिल्ली जा रही एक आर्टिगा कार बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई।

हादसे में कार सवार महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि आर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास मौजूद लोग आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आर्टिगा कार तेज रफ्तार में दिल्ली की ओर जा रही थी। इसी दौरान हवाई पट्टी के सामने अचानक एक बाइक आ गई। बाइक को बचाने की कोशिश में चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सामने चल रहे ट्रक से टकरा गया। सूचना मिलते ही महुआखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

दिल्ली के आजादपुर इलाके से दो बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने दो बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां के आजादपुर इलाके से गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपित ऐसा है जिसे पिछले वर्ष गिरफ्तार कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था, लेकिन वह दोबारा भारत में घुस आया। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से प्रतिबंधित आईएमओ ऐप वाले दो स्मार्टफोन, बांग्लादेशी पहचान पत्र और एक मिर्ची स्प्रे बरामद किया है। उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोहम्मद रुहुल अमीन उर्फ तुली दास और एमडी जीबोन मियां उर्फ लिली के रूप में हुई है। दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं और भारत में रहने के लिए उनके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं मिले। उन्होंने बताया कि 25 जून की सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र के एनएस मंडी, आजादपुर इलाके में दो बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इस आधार पर इंस्पेक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया।

देश में एक साथ दो वेदर सिस्टम सक्रिय होने से होगी झमाझम, गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून अपनी रफ्तार में लौटने की तैयारी कर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने देश में एक साथ दो अहम वेदर सिस्टम के सक्रिय होने का संकेत दिया है। इस हफ्ते बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में बनने वाले इन सिस्टम्स के कारण देश के बड़े हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस बदलाव से उत्तर भारत में लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को राहत मिल सकती है।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

मौसम वैज्ञानिक दो अहम वेदर सिस्टम पर नजर रख रहे हैं, जिनके इस हफ़्ते बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में बनने की उम्मीद है। इनसे देश के बड़े हिस्सों में व्यापक बारिश होगी और उत्तर भारत में लंबे समय से प्रतीक्षित मानसून की स्थिति भी बनेगी। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून अभी तक उत्तर भारत में ठीक से जम नहीं पाया है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान भीषण गर्मी और उमस की चपेट में हैं, और कहीं-कहीं होने वाली आंधी-तूफान से ही थोड़ी-बहुत राहत मिल रही है। हालांकि इस इलाके में नमी लगातार बढ़ी है, लेकिन मानसून का कोई व्यवस्थित सकुर्लेशन न होने के कारण व्यापक बारिश नहीं हो पाई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह स्थिति बदलने वाली है।

पूर्वानुमान अब संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ट्रफ धीरे-धीरे दक्षिण की ओर बढ़ेगा। जैसे-जैसे यह अपनी सामान्य स्थिति के करीब आएगा, वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह बदलाव 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच शुरू होगा, जब मानसून उत्तर भारत में मजबूती से जम जाएगा और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। हालांकि, यह वापसी सिर्फ.मानसून ट्रफ की वजह से नहीं होगी। भारत का मानसून सिस्टम अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। जुलाई का पहला हफ्ता देश के कई हिस्सों के लिए छिटपुट प्री-मानसून बौछारों से निकलकर लगातार और व्यापक मानसूनी बारिश के दौर में प्रवेश करने का समय साबित होगा।

इस नई गतिविधि से उन कई इलाकों में बारिश बेहतर होने की उम्मीद है जहां अब तक बारिश कम हुई है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जिन इलाकों में लंबे समय तक भारी बारिश होगी, वहां स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल-जमाव और ट्रांसपोर्ट में रुकावट की आशंका बनी रहेगी। एक महीने के इंतजार के बाद, भारत का मॉनसून सिस्टम आखिरकार फिर से सक्रिय होता दिख रहा है। अगर अनुमान सही साबित होता हैं, तो जुलाई का पहला हफ्ता छिटपुट प्री-मॉनसून तूफानों से लगातार बारिश की ओर बदलाव का समय हो सकता है।

करीब 500 मिमी हो सकती है बारिश

इस हफ़्ते बंगाल की खाड़ी में लगातार दो कम दबाव वाले क्षेत्र बनने और मध्य भारत से होते हुए जमीन की ओर बढ़ने की उम्मीद है। ये सिस्टम वातावरण में भारी मात्रा में नमी पहुंचाएंगे, जिससे मानसून का सकुर्लेशन मजबूत होगा और पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत में बारिश बढ़ेगी। पश्चिमी तट पर भी एक बार फिर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मुंबई, जहां इस सीजन में पहले ही भारी बारिश हो चुकी है, वहां हफ़्ते के मध्य में बारिश फिर से तेज हो सकती है। अनुमान है कि भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ इलाकों में वीकेंड तक करीब 500 मिमी बारिश हो सकती है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होंगे एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन

वेब वार्ता, मुंबई

देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को अपना नया अंशकालिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। बैंक के निदेशक मंडल ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हालांकि, उनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रभावी होगी।

बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राजीव कुमार को चार वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) नियुक्त करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक होगी। दोनों मंजूरियां मिलने के बाद वह औपचारिक रूप से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। राजीव कुमार का प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत रहे और चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार में वित्त सचिव के पद पर रहते हुए बैंकिंग, वित्तीय सुधारों और आर्थिक नीतियों से जुड़े कई अहम निर्णयों में योगदान दिया था।

एचडीएफसी बैंक में उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब बैंक के पूर्व अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद शीर्ष नेतृत्व का पद रिक्त हो गया था। बैंक प्रबंधन का मानना है कि राजीव कुमार का व्यापक प्रशासनिक अनुभव और वित्तीय क्षेत्र की गहरी समझ संस्थान के दीर्घकालिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राजीव कुमार की नियुक्ति को एक अहम कदम माना जा रहा है।

सेवानिवृत्त हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी

जनरल धीरज सेठ बने नए थल सेना प्रमुख

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। लगभग दो वर्षों तक सेना का नेतृत्व करने के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके स्थान पर जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

सेवानिवृत्ति के अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी और अपनी गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाएगी। अपने विदाई संदेश में जनरल द्विवेदी ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान सेना ने उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर पूरी सतर्कता और तैयारी बनाए रखी। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चल रहे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि सेना की तैनाती पूरी मजबूती और सजगता के साथ जारी रही।

अनुभवी हैं जनरल सेठ

जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना में लगभग चार दशक का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने दिसंबर 1986 में सेना में कमीशन प्राप्त किया था और विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य एवं रणनीतिक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनके नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण और सामरिक क्षमताओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

उन्होंने पश्चिमी सीमा पर सेना की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की दक्षता, संयम और जवाबदेही का महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है। उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रत्येक विषय में सेना ने अनुशासन, स्पष्ट उद्देश्य और जिम्मेदारी के साथ कार्य किया है। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि इस अवधि में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय और अधिक मजबूत हुआ है। तीनों सेनाओं ने साझा रणनीति और आपसी विश्वास के आधार पर बेहतर तालमेल स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति फिलहाल स्थिर अवश्य है, लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। भारतीय सेना किसी भी चुनौती या आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सीमा क्षेत्रों में मजबूत तैनाती बनाए हुए है।

मनरेगा के बकाये और नई वीबी-जी राम जी योजना पर खरगे ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 30 जून (वेब वार्ता)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनरेगा के बकाया भुगतान, नई विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी योजना (वीबी-जी राम जी) और ग्रामीण रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर से जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को कमजोर कर दिया है, राज्यों का बकाया नहीं चुकाया है और नई योजना के जरिए राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है।

खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि लोकसभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार इस साल मार्च तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 17,144.13 करोड़ रुपये बकाया था। इसमें 7,846.25 करोड़ रुपये मजदूरी देनदारी (वेज लायबिलिटी) शामिल है। मजदूरों को उनके हक का भुगतान अब तक क्यों नहीं मिला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक जुलाई से लागू की जा रही वीबी-जी राम जी योजना के बावजूद कई राज्यों को मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के लगभग 700 करोड़ रुपये, झारखंड के करीब 900 करोड़ रुपये सहित तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों के भी भुगतान लंबित हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि नई योजना में कुल खर्च का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को उठाना होगा। खरगे ने कहा कि विभिन्न राज्यों ने इस वित्तीय व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की है और केंद्र को राज्यों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। खरगे ने नई योजना में 60 दिन तक कार्य बंद रखने के प्रावधान पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि कई राज्यों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि इससे किसानों और ग्रामीण मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने मजदूरी दर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कम से कम पांच राज्यों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से मनरेगा के तहत 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की मांग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूरों को सम्मानजनक पारिश्रमिक देने के प्रति गंभीर नहीं है।

सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : गडकरी

नई दिल्ली, वेब वार्ता

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें होती हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।

गडकरी ने यहां मंगलवार को उबर के एक कार्यक्रम में कहा अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुलिस या कानूनी झंझटों में नहीं उलझना पड़ेगा। मदद करने वाले व्यक्ति को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति का किसी भी अस्पताल में इलाज कराने पर डेढ़ लाख रुपये तक का खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि देश में हर साल औसतन पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और करीब 1.80 लाख लोगों की मौत होती है। इन हादसों से देश की जीडीपी का लगभग तीन फीसदी नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं में 66 फीसदी पीड़ित 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। सड़क दुर्घटनाएं न केवल जान लेती हैं बल्कि कई लोगों को स्थायी रूप से अपंग बना देती हैं। गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के चार अहम हिस्से सड़क इंजीनियरिंग, वाहन इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और जन जागरूकता हैं। इनमें सड़क इंजीनियरिंग सबसे महत्वपूर्ण है। इसके तहत देशभर की सड़कों के ब्लैक स्पॉट और पहाड़ी इलाकों के भूस्खलन वाले हिस्सों की पहचान की गई है। इन ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अंडरपास और अन्य ढांचागत निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए वाहनों की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रवर्तन के तहत यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

असम में बाढ़ से 22 हजार से अधिक लोग प्रभावित

यूपी-बिहार और छत्तीसगढ़ में पेड़ व बिजली गिरने से 13 की मौत

वेब वार्ता, नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में मौसम के दोहरे तेवर देखने को मिल रहे हैं। जहां उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में पेड़ गिरने तथा आकाशीय बिजली की घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। सोमवार को लखनऊ समेत 15 जिलों में तेज बारिश हुई। मिर्जापुर में भारी बारिश के बाद एक अंडरपास में करीब तीन फीट पानी भर गया। फिरोजाबाद में ई-रिक्शा पर नीम का पेड़ गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। बस्ती और महराजगंज जिलों में बिजली गिरने से दो लोगों की जान चली गई। बिहार के 15 जिलों में आंधी और बारिश का असर देखा गया। सीतामढ़ी, मुंगेर और पटना में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग झुलस गए। वहीं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बिजली गिरने से दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई।

एक तरफ बारिश और बाढ़ के समाचार हैं तो दूसरी ओर, मानसून की रफ्तार मध्य प्रदेश और गुजरात में थम गई है। 24 जून को इन राज्यों में प्रवेश करने के बाद मानसून आगे नहीं बढ़ सका है। हालांकि, मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक पूरे देश में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में सोमवार को 12 जिलों में बारिश दर्ज की गई।

पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन

पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में लेकू नदी के उफान पर आने से असम के जोनाई क्षेत्र में भीषण बाढ़ आ गई। राष्ट्रीय राजमार्ग-515 भी जलमग्न हो गया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, राज्य के छह जिलों में 22 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। धेमाजी जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां लगभग 16 हजार लोग बाढ़ की चपेट में हैं।

तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज

वहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा के रोहतक में सबसे अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

संपादकीय

वचनबद्धता का रिपोर्ट कार्ड

हिमाचल के सामर्थ्य का दोहरा विभाजन है। एक ओर हम यह चाहते हैं कि सरकारें कर्ज न उठाएं, तो दूसरी ओर मुफ्त बंटवारे का फर्ज निभाएं। ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच केवल एक जीत का अंतर सारे नक्शे नहीं बदल पाता, बल्कि बही खातों का बहाव बरकरार रहता है।

बड़े सोच के पैरामीटर भी बड़े करने होंगे, वरना धरातल पर आकर योजनाओं का बिखराव ही होगा। हिमाचल की दृष्टि में माई बाप मानने की संगत और ऐसी सियासत पैदा हुई है कि सारे हुजूर सत्ता में नजर आते हैं। इसलिए यहां भी वोट का आरक्षण फरियादी हो कर गारंटियां मांगता है। यहां निर्णायक होने की वजह सरकार से प्राप्तियां हैं और इसीलिए समीक्षाएं अकसर फेस वैल्यू पर होती हैं।

बहरहाल चुंबकीय आकर्षण यह कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पिछड़ेपन के पत्तन तोड़ कर बड़ा भंगाल पहुंचे, तो कारवां महिलाओं तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने अपने कर्म और फर्ज का युक्तिकरण करते हुए अतिदुरुह क्षेत्रों के पत्थर तोड़े हैं और इसी कड़ी को बड़ा भंगाल से जोड़ते वह वचनबद्धता का रिपोर्ट कार्ड टांग देते हैं। सवाल यह भी है कि सरकार के मायने सिर्फ इतने ही बचे हैं कि हिमाचली समाज अपने ही स्वार्थ की आरती उतारे। बड़ा भंगाल में पंद्रह सौ रुपए की पुड़िया में सदियों का मर्म छुपा है, कोई ताकीद करे कि इस तरह रहम बहता है। कई दृष्टि से हिमाचल में बड़ा भंगाल अति पिछड़ा हो जाता है। जब सर्दियों के मौसम में बर्फ की सफेद चादर के नीचे दर्द की पट्टी उभरती है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से यह क्षेत्र लाहौल-किन्नौर से अति दुष्कर नजर आता है, तो क्या कोई एक सुरंग यहां के पथ को हमेशा बहाल नहीं कर सकती। बड़ा भंगाल की गुल्लक बैजनाथ में आकर खाली होती है, तो इसे हमेशा भरा हुआ रखने के लिए मख्यमंत्री का शपथपत्र काम आएगा।

दरअसल आर्थिक दुरुहता के खिलाफ राज्य की प्राथमिकताएं कम विकसित क्षेत्रों पर आकर ही तय होंगी और इस दृष्टि से रात्रि विश्राम की पहल करके मुख्यमंत्री सुक्खू ने पांगी-बड़ा भंगाल जैसे इलाकों की नब्ज टटोली है। इसी परिप्रेक्ष्य में कभी बीबीएन जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम, कई खामियों को दुरुस्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर शिमला की तर्ज पर जिला मुख्यालयों, प्रमुख शहरों व धार्मिक नगरियों में सुबह की सैर करें, तो मालूम होगा कि कितने आवारा पशु शहरों के अमन को बर्बाद कर रहे हैं या बंदरों के नाच ने नागरिकों का जीना हराम किया है। आश्चर्य यह कि जिलाधीश कार्यालयों में जहां फूल उगने चाहिएं, वहां खड़पतवार चिढ़ा रहे होते हैं। ट्रैफिक जाम में कई कस्बे फंसे रहते हैं। इतना ही नहीं जो क्षेत्र स्थानीय निकायों के हवाले होने चाहिएं, वहां पंचायतें सिर्फ नागरिकों को मुजरिम बना रही होती हैं। उदाहरण के लिए छावनी क्षेत्रों से आजाद होकर अगर दशकों की शहरी परिपाटी को पंचायतों में बांटा जा रहा है, तो यह लज्जाजनक उपलब्धि है। सबसे बड़े योल छावनी से नागरिक क्षेत्र बाहर करके न जाने किस सियासत की संतुष्टि हुई, लेकिन अब चार पंचायतों में विघटित क्षेत्र गंदगी, नागरिक सुविधाओं की अफरातफरी और मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं में दरिद्र हो गए। आजादी के पहले से योल छावनी प्रशासन इन क्षेत्रों में सुरक्षित पानी, साफ आबोहवा और व्यवस्थित जीवन की गारंटी दे रहा था, तो अब गांव की दहलीज पर आटा गीला करके क्या मिलेगा। हिमाचल की प्रगति, आर्थिक दुरुहता और पिछड़ेपन को दूर करके साबित होगी, तो धर्मशाला से चंद कदम दूर योल छावनी के पिछड़े ग्राम नगर निगम की परिधि में समाहित होने चाहिएं।

सरकार के 12 साल : वे अजेय क्यों हैं?

26 मई 2014 को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और पहली पूर्ण गैर-कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया। जहां आजादी के बाद के शुरूआती तीन दशकों में भारत की आर्थिक विकास दर 3 से 4 प्रतिशत के बीच रही, वहीं पश्चिमी एशिया और दूसरी जगहों के छोटे देशों ने तकनीकी तरक्की के साथ-साथ बहुत तेजी से आर्थिक विकास किया। जहां भारत को एक विकासशील देश माना जाता रहा, वहीं ये छोटे देश ह्यएशियन टाइगर्सह्न के तौर पर मशहूर हो रहे थे। गरीबी कम होने की रफ्तार भी बहुत प्रभावशाली नहीं थी। एक खास ढांचे के आधार पर गरीबी का पहला आकलन 1973-74 में किया गया, जब योजना आयोग ने गरीबी रेखा की अवधारणा पेश की, जिसके मुताबिक 54.9 प्रतिशत आबादी इसके नीचे रह रही थी। हालांकि समय के साथ गरीबी रेखा की परिभाषाएं बदलती रहीं, लेकिन 2012-13 में भी 21.9 प्रतिशत आबादी- यानी 269.3 मिलियन (26.93 करोड़) लोग- गरीबी रेखा से नीचे माने जाते थे। इस बीच, वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के मुताबिक- जिसमें 2012-13 में रोजाना 1.25 अमरीकी डालर से कम कमाने वालों को घोर गरीबी में रहने वाला माना गया था- दुनिया के 1.2 अरब गरीब लोगों में से एक-तिहाई, यानी 40 करोड़ लोग, भारत में थे। हालांकि, 2025 तक, वर्ल्ड बैंक की परिभाषा- जिसे बढ़ाकर 2.15 अमरीकी डालर प्रति दिन कर दिया गया था- के आधार पर घोर गरीबी में रहने वाली कुल आबादी का हिस्सा घटकर सिर्फ 2.3 प्रतिशत रह गया है।

अमरीकी डालर प्रति दिन की ज्यादा नई परिभाषा के तहत भी, यह आंकड़ा सिर्फ 5.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसे निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई। आज भारत और दुनिया भर में गरीबी की एक ऐसी परिभाषा मौजूद है जो इस घोर गरीबी से आगे जाती है, यानी ह्यबहुआयामी गरीबीह्न। इसे मापने में दस पैमाने शामिल हैं : दो शिक्षा से जुड़े, दो स्वास्थ्य से, और बाकी छह में आवास, बिजली, स्वच्छता, खाना पकाने के लिए साफ ईंधन, पीने का पानी और संपत्ति का मालिकाना हक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार, 2015-16 और 2019-21 के बीच, सिर्फ पांच सालों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 0.117 से घटकर 0.069 हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में अनुमानित 11.28 फीसदी हो गई, जो एक दशक में लगभग 18 प्रतिशत अंकों की कमी को दशार्ता है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि भारत में न केवल घोर गरीबी में बल्कि बहुआयामी गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई है। आम तौर पर, कई आर्थिक विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं कि यदि आर्थिक विकास के दौर में गरीबी कम करने के प्रयासों के तहत संसाधनों के पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो विकास की गति धीमी हो सकती है। इसलिए, उनका मानना है कि आर्थिक विकास के चरणों के दौरान पुनर्वितरण को प्राथमिकता देना उचित नहीं है। इस विचार को मानने वाले अर्थशास्त्री, जो मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार के समर्थक भी हैं, उनमें न केवल वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विशेषज्ञ शामिल हैं, बल्कि प्रो. जगदीश भगवती और उनके सह-लेखक प्रो. अरविंद पनगढ़िया जैसी बड़ी हस्तियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसे अर्थशास्त्रियों की दलीलों के बावजूद, न केवल भारत ने आर्थिक विकास दर ऊंचा रखा, बल्कि बहुआयामी और अत्यधिक गरीबी को कम करने में भी बड़ी सफलता हासिल की। कोविड-19 के कारण एक साल के झटके के बावजूद, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी लगभग 7.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ती रही। हमें यह भी पहचानना होगा कि देश में असमानता और गरीबी को कम करने में कौनसी नीतियां असरदार साबित हुईं। यह समझना जरूरी है कि जहां आजादी के बाद के शुरूआती सालों में गरीबी कम होने की रफ्तार बहुत धीमी थी, वहीं मोदी के राज में गरीबी कम करने की दिशा में कैसे बड़ी प्रगति हुई, जिससे विकास पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समावेशी हो गया।

वित्तीय समावेशन : आजादी और 2014 के बीच विकास की कई कोशिशों के बावजूद, देश में वित्तीय समावेशन के मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसका सबूत यह है कि 2014 और 2026 के बीच 580 मिलियन (58 करोड़) जन धन खाते खोले गए। और इन जन धन खातों में कुल 3 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए थे। जन धन खाते जीरो बैलेंस खाते होते हैं, यानी इन्हें खोलने के लिए किसी शुरूआती जमा राशि की जरूरत नहीं होती। वित्तीय समावेशन का एक और पहलू ह्यप्रत्यक्ष लाभ अंतरणह्न (डीबीटी) है। पहले, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित फंड का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। जन-धन खाते खुलने के बाद, उन्हें आधार (यूआईडी) और मोबाइल फोन नंबरों से जोड़ा गया, नतीजतन अब पूरी कल्याणकारी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पैसे के बीच में ही गायब होने या चोरी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन का एक और पहलू ह्यडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरह्न (डीबीटी) है। पहले, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित फंड का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार के कारण सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। हालांकि, जन-धन खाते खुलने के बाद, उन्हें आधार (यूआईडी) और मोबाइल फोन नंबरों से जोड़ा गया। नतीजतन अब पूरी कल्याणकारी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पैसे के बीच में ही गायब होने या चोरी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रक्रिया को ह्यजैम त्रयह्न के नाम से जाना जाता है- जिसमें जन-धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल हैं, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता के दम पर हासिल किया है।

महिलाओं के लिए खास : आवास, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, बिजली और पानी : आजादी से लेकर 2014 तक के सफर की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह थी कि 2014 में भी देश में 12.3 करोड़ लोग कच्चे (अस्थायी) घरों में रहते थे, जबकि 31.7 करोड़ लोग अर्ध-स्थायी घरों में रहते थे। इसके विपरीत, सिर्फ पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ और शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाए गए हैं, और उसके अलावा 1.2 करोड़ घर या तो मंजूर हो चुके हैं या बन रहे हैं। खुले में शौच करने की मजबूरी को लंबे समय से देश के लिए एक बड़ा कलंक माना जाता था। यह संतोष की बात है कि 2014 के बाद से देश भर में 12.8 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे खुले में शौच की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान हो गया है। आज, देश में लगभग पूरी तरह से बिजली पहुंच चुकी है, और ह्यहर घर नल से जलह्न योजना के तहत ज्यादातर इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध हो गया है। स्वच्छ ईंधन की बात करें तो, जहां 2014 में केवल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वहीं अब यह संख्या 34 करोड़ से ज्यादा हो गई है। खास बात यह है कि इनमें से 10 करोड़ नए कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए, जिसके जरिए गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर और गैस स्टोव उपलब्ध कराए गए। आवास, पानी, बिजली, स्वच्छता सुविधाएं और एलपीजी कनेक्शन ऐसी उपलब्धियां हैं जिनसे पूरे समाज और खासकर गरीबों को फायदा हुआ है। हालांकि, महिलाओं का सबसे ज्यादा सशक्तिकरण हुआ है क्योंकि सुविधाएं मिलने से वंचित परिवारों की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है।

डा. अश्वनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मोदी के नाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। इसके साथ ही पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, जिन्हें अभी तक 34 देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा और इस सम्मान को लेकर विवादों का पिटारा भी भारत में खुलता हुआ नजर आ रहा है। सेशेल्स टैक्स हेवन देश है। इस देश की आबादी मात्र 1.1 लाख है। यह अफ्रीका का सबसे छोटा टापू है। इसका कुल क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर है। इसकी गिनती समृद्ध देश के रूप में होती है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टैक्स हैवन देश के रूप में है। यह देश मत्स्य पालन, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं के लिए सारी दुनिया के देशों में पहचाना जाता है। यहां पर मुश्किल से 7 से 8000 भारतीय रहते हैं। इसमें से कुछ वर्षों में लगभग 2000 भारतीयों ने यहां की नागरिकता ली है। शेष भारतीय यहां पर जन्मजात रह रहे हैं। पनामा पेपर लीक में भी इस देश का नाम आया था। उस समय भी इसमें भारतीय नागरिकों के नाम थे। जिन्होंने अपना काला धन वहां जमा किया था। 2014 में जब केंद्र की सरकार बदली, उसके बाद यह माना जा रहा था, सरकार काला धन वापस लाने के लिए विशेष प्रयास करेगी। मोदी सरकार ने पनामा पेपर लीक मामले में जिन लोगों के नाम शामिल थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कालाधन बड़ा चुनावी मुद्दा था। इस समय नरेन्द्र मोदी ने विदेशों में जमा कालाधन वापिस लाने का वायदा किया था। यह भी कहा था, हर परिवार को 15 लाख रूपया यों ही मिल जाएंगे। सेशेल्स जैसे देश से भारतीयों का जमा कालाधन वापस लाने

का कोई प्रयास मोदी सरकार ने नहीं किया। उल्टे विगत वर्षों में जिस तरह से टैक्स हेवन देशों का पैसा भारत के शेयर बाजार एवं कारोबार में निवेश किया गया है, उसको लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में विनोद अडानी का नाम भी सामने आया था। सेबी और सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में बंद कर के रखा है।

इतने छोटे से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, लगभग तीन दिन तक रुकना, भारत में चर्चा का विषय बन गया है। भारत सरकार का कहना है, सेशेल्स हिंद महासागर का हिस्सा है। समुद्र का एक छोटा द्वीप होते हुए भी भारत के लिए सामरिक और समुद्री व्यापार के लिए उसका बड़ा महत्व है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से सेशल्स को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रही है। पनामा पेपर लीक मामले तथा शेयर बाजार में निवेश को लेकर कई आरोप सामने आ चुके हैं। भारत सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। भारत में मोदी सरकार के लिए कई चुनौतियां सामने हैं। अयोध्या के राम मंदिर दान एवं चढ़ावे का मामला इस समय चरम पर है। कुछ ही दिनों बाद मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन शुरू हो गए हैं। विपक्ष बहुत आक्रामक है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स जाना विवादों में आ गया है। उन्हें जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक और पहली बार नया सम्मान दिए जाने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। एक छोटे से टैक्स हेवन देश की यह यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगे चलकर कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न ना कर दे, इसको लेकर तरह-तरह की आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम करें, उन्हें किसी भी स्तर पर कोई नुकसान हो, यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों की संख्या कम नहीं है। इस तरह के विरोध होते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के विरोध पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। सेशेल्स यात्रा को लेकर जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह के नुकसान के रूप में होगा, यह संभव ही नहीं है।

(लेखक- सनत जैन)

स्कूल प्रबंधन समिति : शिक्षा की नई उम्मीद

यदि किसी राष्ट्र का भविष्य देखना हो तो उसके विद्यालयों को देखिए। यह केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि शिक्षा का शाश्वत सत्य है। विद्यालय किसी भी राष्ट्र की आत्मा होते हैं। यहीं से संस्कार, अनुशासन, नागरिक चेतना और जिम्मेदार भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा केवल सरकार या शिक्षकों का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है।

आज जब हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नई स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन हो रहा है, तब यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों में जनविश्वास, उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाने का सुनहरा अवसर है। भारत में विद्यालयों के प्रबंधन में जनभागीदारी का विचार नया नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में 1882 के हंटर आयोग ने पहली बार यह सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में स्थानीय निकायों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। यद्यपि उस समय औपचारिक स्कूल प्रबंधन समितियां अस्तित्व में नहीं थीं, फिर भी यह स्वीकार किया गया कि विद्यालय केवल सरकार के भरोसे नहीं चल सकते। 1904 की भारतीय शिक्षा नीति तथा 1919 के भारत शासन अधिनियम ने भी स्थानीय संस्थाओं और समाज की भूमिका को प्रोत्साहित किया। यही वह दौर था जब अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ने की सोच ने आकार लेना शुरू किया।

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया। 1964-66 के कोठारी आयोग ने स्पष्ट कहा कि विद्यालय तभी सफल होंगे जब समाज उन्हें अपना संस्थान माने। इसी सोच के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने सामुदायिक सहयोग और समान अवसरों पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 के संशोधित कार्यक्रम ने विद्यालयों के प्रबंधन में अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को और अधिक महत्व दिया। आगे चलकर सर्व शिक्षा अभियान के दौरान विद्यालय शिक्षा समितियों और ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से अभिभावकों को नामांकन बढ़ाने, विद्यालय विकास और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस व्यवस्था को कानूनी आधार बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से मिला, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके तहत प्रत्येक सरकारी विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य किया गया, जिसमें अधिकांश सदस्य अभिभावक रखने का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य स्पष्ट था- विद्यालयों का संचालन जनता की भागीदारी से हो और प्रत्येक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी केवल शिक्षक की नहीं, बल्कि पूरे समाज की बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विद्यालय को समाज का केंद्र मानते हुए शिक्षक, अभिभावक, पंचायत, पूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के बीच मजबूत साझेदारी पर बल दिया। इसी दिशा में शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 2026 में जारी स्कूल प्रबंधन समिति दिशा-निर्देश विद्यालय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार माने जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों में पारदर्शिता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, मासिक बैठकें, तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना, महिला प्रतिनिधित्व, सीखने के परिणामों की समीक्षा तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एकीकृत एसएमसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिससे विद्यालय प्रबंधन अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बन सके। हिमाचल प्रदेश लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में रहा है। ऊंची साक्षरता दर और दूरस्थ क्षेत्रों तक विद्यालयों की पहुंच इसकी पहचान है। फिर भी आज सरकारी विद्यालय घटते नामांकन, विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट, निजी विद्यालयों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और पलायन जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

इन परिस्थितियों में एसएमसी केवल एक समिति नहीं, बल्कि विद्यालय और समाज के बीच विश्वास का सेतु बन सकती है। सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले अधिकांश बच्चे ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। उनके माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन-रात परिश्रम करते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण विद्यालय से नियमित संवाद नहीं हो पाता। कई बार यह सोच भी बन जाती है कि बच्चों की शिक्षा केवल शिक्षक की जिम्मेदारी है। जबकि प्रसिद्ध शिक्षाविद् मारिया मोंटेसरी का मानना था कि ह्यबच्चे का विकास तभी संभव है जब घर और विद्यालय एक-दूसरे के सहयोगी बनें।ह्न वास्तव में जागरूक अभिभावक ही किसी भी विद्यालय की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। आज युवाओं में बढ़ता नशा समाज के सामने गंभीर चुनौती है। इसका समाधान केवल पुलिस या कानून नहीं कर सकते। इसकी शुरूआत घर से होती है और रोकथाम भी घर से ही संभव है। यदि अभिभावक अपने बच्चों की दिनचर्या, मित्रों, मोबाइल के उपयोग और व्यवहार पर संवेदनशीलता से ध्यान दें, उनसे नियमित संवाद रखें और विद्यालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें, तो अनेक बच्चे नशे की गिरफ्त में जाने से बच सकते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति नशा निवारण अभियान, खेलकूद, योग, सांस्कृतिक गतिविधियों और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को सकारात्मक वातावरण दे सकती है। जागरूक अभिभावक और सक्रिय एसएमसी मिलकर नशे के विरुद्ध सबसे प्रभावी सामाजिक अभियान बन सकते हैं। डिजिटल युग ने शिक्षा के नए अवसर दिए हैं, लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन खेलों ने बच्चों के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। ऐसे में एसएमसी अभिभावकों को डिजिटल अनुशासन, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए प्रेरित कर सकती है। आज विद्यालयों को केवल परीक्षा परिणामों से नहीं, बल्कि बच्चों के चरित्र, व्यवहार और जीवन मूल्यों से भी आंकने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का मूल लक्ष्य बताया। बहरहाल, एसएमसी का गठन अत्यंत जरूरी है।

सिकंदर बंसल
शिक्षाविद

आलेख

क्या हम विकास और विनाश के बीच संतुलन साध पाएंगे?

वेनेजुएला में हाल में आए भीषण भूकम्प ने केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को झकझोर दिया है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या समय के साथ बदलती रही हो, लेकिन त्रासदी की भयावहता निर्विवाद है। हजारों परिवार अपने प्रियजनों को खोने की असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक अवसर पर पूरी दुनिया संवेदना व्यक्त करती है, राहत सामग्री भेजती है, सहायता अभियान चलाती है, लेकिन एक प्रश्न बार-बार हमारे सामने खड़ा हो जाता है-क्या हम हर बड़ी आपदा से कोई स्थायी सबक सीखते हैं या फिर कुछ दिनों की चर्चा और शोक के बाद सब कुछ भुलाकर पुन: उसी लापरवाह विकास-यात्रा एवं प्रकृति की घोर उपेक्षा पर निकल पड़ते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कभी कैलेंडर देखकर नहीं आतीं। वे न देश चुनती हैं, न मौसम और न समय। जब धरती कांपती है, नदियां उफान पर आती हैं, पहाड़ दरकते हैं या समुद्र विकराल रूप धारण कर लेता है, तब विकास के बड़े-बड़े दावे, ऊंची-ऊंची इमारतें और तकनीकी उपलब्धियों का अहंकार कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाता है। ऐसे समय में किसी देश की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि उसकी पूर्व तैयारी, संवेदनशील शासन व्यवस्था और जागरूक नागरिक होते हैं।

वेनेजुएला की त्रासदी ने एक सकारात्मक पक्ष भी सामने रखा। आधुनिक तकनीक ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को भूकम्प के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले चेतावनी दी। सुनने में यह समय बहुत कम प्रतीत होता है, लेकिन आपदा की घड़ी में यही कुछ सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर सकते हैं। विज्ञान इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रारंभिक चेतावनी तंत्र अधिक सटीक, अधिक तेज और अधिक व्यापक बनाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। भारत के लिए यह विषय केवल एक अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं है। हमारा देश स्वयं भूकम्प, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, चक्रवात और सुनामी जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। 1993 का लातूर भूकम्प, 2001 का भुज भूकम्प, 2004 की सुनामी, 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2023 की जोशीमठ भू-धंसाव की घटनाएं तथा हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। इन सभी घटनाओं का एक ही संदेश है-प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता।

वैज्ञानिक आज भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस दिन, किस समय और किस स्थान पर भूकम्प आएगा, लेकिन वे वर्षों से यह चेतावनी अवश्य देते रहे हैं कि भारत का लगभग साठ प्रतिशत भूभाग किसी न किसी स्तर के भूकम्पीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। हिमालयी क्षेत्र, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-पूर्व, गुजरात और अनेक अन्य क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि भूकम्प की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो भी पूर्व तैयारी पूरी तरह संभव है। दुर्भाग्य यह है कि हम तैयारी की अपेक्षा आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर अधिक ध्यान देते हैं। आज देश के लगभग हर शहर में कंक्रीट के विशाल जंगल तेजी से खड़े हो रहे हैं। बहुमंजिला आवासीय परिसर, व्यावसायिक भवन, गगनचुंबी टावर और स्मार्ट सिटी विकास की नई पहचान बन चुके हैं। मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अब जयपुर जैसे शहर भी ऊंची-ऊंची इमारतों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन भवनों की मजबूती केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए है या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए भी?

किसी भी भवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब धरती कांपती है, जब अचानक बाढ़ आती है, जब तेज हवाएं चलती हैं या जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। यदि उस समय भवन लोगों की जान बचा सके, तभी उसे वास्तविक विकास का प्रतीक माना जाना चाहिए। केवल ऊंचाई, चमक-दमक और आधुनिक सुविधाएं किसी भवन को सुरक्षित नहीं बनातीं। भारत में भूकम्परोधी निर्माण के लिए मानक और नियम मौजूद हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। समस्या नियमों की कमी नहीं, बल्कि उनके अनुपालन की है। क्या प्रत्येक बहुमंजिला इमारत वास्तव में उन्हीं मानकों के अनुरूप निर्मित हो रही है? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होती है? क्या निर्माण के बाद संरचनात्मक सुरक्षा का स्वतंत्र परीक्षण किया जाता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, तो चिंता स्वाभाविक है।

निर्माण क्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। अनेक बार भू-माफिया, बिल्डर लॉबी और लाभ-लोलुप तत्व पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए हरित क्षेत्रों, जलाशयों, नदी तटों और भू-संवेदनशील क्षेत्रों तक में निर्माण कर देते हैं। बाद में यही निर्माण किसी त्रासदी का कारण बनते हैं। नोएडा में अवैध रूप से निर्मित सुपरटेक ट्विन टावरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया जाना इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई निर्माण अवैध था, तो उसे बनने की अनुमति किसने दी? निर्माण पूरा होने तक प्रशासन मौन क्यों रहा? क्या विकास के नाम पर कुछ लोगों के आर्थिक लाभ के लिए लाखों नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाला जा सकता है? यह केवल कानूनी प्रश्न नहीं, बल्कि नैतिक प्रश्न भी है। शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर विकास न्यासों तथा भवन निर्माण की अनुमति देने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी केवल नक्शों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं हो सकती। प्रत्येक निर्माण की तकनीकी, पर्यावरणीय और संरचनात्मक जांच अत्यंत कठोरता से की जानी चाहिए। सुरक्षा मानकों का पालन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की रक्षा का दायित्व है।

एक अन्य गंभीर चिंता जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की है। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करना, जंगलों का अंधाधुंध विनाश, अतिक्रमण, खनन और अनियोजित शहरीकरण ने प्रकृति के संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप भूस्खलन, अचानक बाढ़, शहरी जलभराव और जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बार-बार आने वाली त्रासदियां हमें चेतावनी दे रही हैं कि विकास का मॉडल प्रकृति-विरोधी नहीं, बल्कि प्रकृति-संगत होना चाहिए। यह मान लेना भी खतरनाक है कि जिस क्षेत्र में पहले कभी बड़ा भूकम्प नहीं आया, वहां भविष्य में भी खतरा नहीं होगा। धरती के भीतर क्या हलचल चल रही है, इसका पूरा रहस्य आज भी मानव नहीं जान पाया है। इसलिए केवल पुराने अनुभवों के आधार पर किसी क्षेत्र को पूर्णत: सुरक्षित मान लेना आत्मघाती हो सकता है। आज भवन निर्माण केवल भूकम्प को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता। अत्यधिक वर्षा, शहरी बाढ़, तेज हवाएं, तापमान में वृद्धि और अन्य प्राकृतिक चुनौतियों को भी नगर नियोजन का हिस्सा बनाना होगा। भविष्य के शहरों को बहुस्तरीय सुरक्षा की अवधारणा के आधार पर विकसित करना समय की मांग है। आपदा आने के बाद राहत और पुनर्वास पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने की अपेक्षा पहले से सुरक्षा पर निवेश करना कहीं अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण है। सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है। नागरिकों को भी आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक होना होगा। विद्यालयों, कार्यालयों और आवासीय परिसरों में नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। आधुनिक चेतावनी प्रणालियों को गांवों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे होने वाली तबाही को काफी हद तक कम अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक, कठोर निगरानी, पारदर्शी प्रशासन और जागरूक नागरिकों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। प्रकृति कभी यह नहीं पूछती कि इमारत कितनी महंगी है, किस बिल्डर ने बनाई है या वह किस शहर में खड़ी है। वह केवल उसकी मजबूती और मानव की दूरदर्शिता की परीक्षा लेती है। वेनेजुएला का भूकम्प एक चेतावनी है-विकास की परिभाषा बदलने की। विकसित राष्ट्र वह नहीं होगा जिसके पास सबसे ऊंची इमारतें हों, बल्कि वह होगा जिसके पास सबसे सुरक्षित इमारतें, सबसे जिम्मेदार नगर नियोजन, सबसे संवेदनशील शासन और सबसे सजग नागरिक हों। क्योंकि आपदा आने के बाद राहत देना व्यवस्था की मजबूरी होती है, लेकिन आपदा आने से पहले तैयारी करना एक दूरदर्शी राष्ट्र की संस्कृति और जिम्मेदार शासन की पहचान है।

(लेखक- ललित गर्ग)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

कुलपति प्रो. सरोज शर्मा की पुस्तक वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का विमोचन

नई दिल्ली,वेब वार्ता। रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा की पुस्तक वैल्यू एंड पीस एजुकेशनः फ्यूचर रोडमैप का मंगलवार को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्व विद्यालय (आईपीयू) के कुलपति डॉ. महेश वर्मा ने विमोचन किया। इस अवसर पर डॉ. महेश वर्मा ने कहा आज का सामाजिक ताना-बाना जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, उसे देखते हुए इस तरह की पुस्तक की अहमियत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों का तेजी से अपरदन हो रहा है जिससे पूरी दुनिया में शांति की अवधारणा खतरे में है।

पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्य तिथि पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली,वेब वार्ता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को डॉ. साहिब सिंह वर्मा की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के साथ साहिब सिंह वर्मा के पुत्र एवं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, महामंत्री विष्णु मित्तल, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष सागर त्यागी, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अनीस अब्बासी, प्रवक्ता यासिर जिलानी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

समयपुर बादली स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी बेहतर परिवहन सुविधाएं

नई दिल्ली (वेब वार्ता)। बाहरी दिल्ली के समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन पर बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डीएमआरसी यहां जल्द नए बदलाव करने जा रही है। इस जगह पर मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन बेहद पास होने के चलते रोजाना बड़ी संख्या में यात्री यहां से सफर करते हैं। ऐसे में डीएमआरसी इस स्टेशन को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए डीएमआरसी ने रेलवे, ट्रैफिक पुलिस, पीडब्लयूडी, परिवहन विभाग नगर निगम आदि के साथ मौके का निरीक्षण किया है। जानकारी के अनुसार राजधानी में बेहतर परिवहन व्यवस्था को लेकर बीते मई माह में पीएमओ ने दिल्ली के विभिन्न विभागों की एक बैठक ली थी। इस बैठक में डीएमआरसी की तरफ से बताया गया कि परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वह समयपुर बादली स्टेशन को एक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करेंगे।

दिल्ली एयरपोर्ट पर 1.47 करोड़ का सोना जब्त किया गया

नई दिल्ली,वेब वार्ता

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को एक बड़े सोने की तस्करी का मामला हाथ लगा है। दुबई से आ रहे बांग्लादेशी ट्रांजिट यात्री ने एयरपोर्ट के वॉशरूम के फ्लश बटन के अंदर 1.47 करोड़ रुपये मूल्य का सोना छिपा रखा था। कस्टम अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 26 जून को दुबई से दिल्ली पहुंचे और 27 जून को ट्रांजिट में थे। इन दिनों गोल्ड स्मगलर तरह-तरह के पैतरे आजमा रहे हैं।

सोना वॉशरूम के फ्लश बटन में छिपाकर लाया गया था

संदिग्ध यात्री की 'संदिग्ध ट्रांजिट ट्रैवल पैटर्न' को देखते हुए उसे अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर एरिया में चिन्हित किया गया। उसके बाद उसे डिपार्चर एरिया के एक वॉशरूम के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान यात्री ने कबूल किया कि उसने तीन अंडाकार पीले रंग के पाउच एक गहरे नीले मोजे में लपेटकर वॉशरूम के फ्लश बटन के अंदर छिपा दिए थे।

अधिकारियों ने तीनों पाउच बरामद कर लिए। इन पाउच में सोने का पेस्ट था, जिससे 1,141.5 ग्राम शुद्ध सोना निकाला गया। बरामद सोने की कीमत करीब 1,46,64,211 रुपये (लगभग 1.47 करोड़ रुपये) बताई गई है। कस्टम विभाग ने इस सोने को कस्टम एक्ट 1962 के तहत जब्त कर लिया है। यात्री के खिलाफ सोने की तस्करी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।यह घटना एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था की चुस्ती को दिखाती है, साथ ही तस्करों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों को भी उजागर करती है।

दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया शुरू

13 हजार बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन

दिल्ली में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके तहत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) एक महीने तक राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटेंगे।

नई दिल्ली,वेब वार्ता

अधिकारियों ने बताया कि बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे सुबह जल्दी और शाम के समय, जब लोग घर पर मौजूद हों, घर-घर जाकर सत्यापन करें। इसके लिए शनिवार और रविवार को भी अभियान चलाया जाएगा।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, एक महीने तक चलने वाले घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान के लिए 13,000 से अधिक बीएलओ तैनात किए गए हैं। यह अभियान 29 जुलाई को समाप्त होगा। दिल्ली में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से इस घर-घर सर्वेक्षण में भाग ले रहे हैं, ताकि लोगों को प्रपत्र भरने और जमा कराने में सहायता मिल सके। राष्ट्रीय राजधानी में सात लोकसभा क्षेत्रों और 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 13,033 मतदान केंद्र हैं।

एसआईआर के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां देंगे, जिन्हें 2002 में हुए पिछले एसआईआर के आधार पर अपनी जानकारी भरनी होगी। इनमें से एक प्रति रसीद पावती के रूप में मतदाता के पास रहेगी, जबकि दूसरी प्रति बीएलओ को वापस करनी होगी। गणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। हर मतदाता को यह गणना प्रपत्र भरना होगा ताकि सात अक्टूबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में उनके नाम शामिल हो सकें। सीईओ कार्यालय के मुताबिक, जो लोग गणना प्रपत्र नहीं भरेंगे, उनके नाम पांच अगस्त को जारी होने वाली मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। घर-घर सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई घर बंद मिलता है, तो संबंधित बीएलओ वहां कम से कम तीन बार जाएगा।

ऑनलाईन भी कर सकते हैं जमा

दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 77.11 लाख पुरुष और 67.98 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 1,024 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 76,155 है। यदि कोई मतदाता 2002 के बाद दिल्ली में आकर बस गया है, तो उसे अपने मूल राज्य में हुई पिछली एसआईआर की जानकारी भी प्रपत्र में भरनी होगी, जहां वह पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत था। सभी राज्यों की मतदाता सूचियां निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। मतदाता अपने गणना प्रपत्र का विवरण ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग घोटाला: आम आदमी पार्टी बोली, मुख्य आरोपित राजीव रंगीला की हो गिरफ्तारी

नई दिल्ली,वेब वार्ता। आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कथित 650 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य विभाग घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2 जून को दर्ज एसीबी की एफआईआर में निजी कारोबारी राजीव रंगीला का नाम प्रमुखता से दर्ज है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है।

पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारद्वाज ने कहा कि एसीबी की एफआईआर एक ही व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है। उन्होंने बताया कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राजीव रंगीला ने विभिन्न नामों से कई कंपनियां बनाकर सरकारी खरीद प्रक्रिया को प्रभावित किया और स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों, दवाइयों तथा अन्य सामग्री की खरीद में भ्रष्टाचार किया।

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि टेंडरों की तकनीकी और वित्तीय शर्तें इस प्रकार तैयार कराई जाती थीं कि सामान्य कंपनियां भाग ही नहीं ले सकें और अंततः संबंधित कंपनियों को ही ठेका मिल जाए। भारद्वाज ने कहा कि बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों की सरकारी खरीद कई गुना अधिक कीमत पर कराई गई, जिसके कारण से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एफआईआर में राजीव रंगीला का नाम कई बार दर्ज है और उसे नामजद आरोपित बनाया गया है। इसके बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गयी जो कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने सरकार से सवालिया लहजे में पूछा कि यदि पूरे मामले का राजीव रंगीला है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।

भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस दावे को भी खारिज किया कि जिसमें कहा गया है कि यह मामला उनकी शिकायत पर दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि एफआईआर में कहीं भी मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायत का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसे सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन के आधार पर दर्ज किया गया बताया गया है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि राजीव रंगीला पूर्ववर्ती सरकारों के समय से स्वास्थ्य विभाग में सक्रिय रहा है और उनकी सरकार के कार्यकाल में भी उसने प्रभाव बनाने का प्रयास किया था, जिसे तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने सफल नहीं होने दिया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हटाए गए मतदाताओं की पूरी जानकारी राजनीतिक दलों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आप ने सरकार से इस पूरे मामले में राजीव रंगीला की शीघ्र गिरफ्तारी तथा एसीबी जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

नाबालिग बेटा बनेगा पिता का 'लाइफ सेवर', दिल्ली हाई कोर्ट ने दी लीवर दान करने की इजाजत

नई दिल्ली,वेब वार्ता। बीमार पिता को लीवर का एक हिस्सा दान करने की 17 वर्षीय नाबालिग बेटे की अपील को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता नाबालिग है, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वह अपनी मर्जी, प्यार और लगाव के कारण अपने पिता को अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने को तैयार है। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का मानना है कि न्याय के नजरिए से, प्रस्तावित लिवर डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति देना ही सबसे सही है, क्योंकि अगर कोर्ट ऐसी अनुमति नहीं देता है, तो याचिकाकर्ता के पिता की जान जा सकती है। अपनी मां के माध्यम से याचिका दायर कर नाबालिग ने कहा कि उसके पिता गंभीर लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं और वसंत कुंज स्थित आइएलबीएस में इलाज चल रहा हे। अदालत ने दिल्ली सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामा को रिकार्ड पर लिया, जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल व संबंधित अधिकारियों ने लीवर ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी है।

गांधी नगर पुलिस ने चोरी का खुलासा किया, नकदी और स्कूटी बरामद

नई दिल्ली, वेब वार्ता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गांधी नगर थाना पुलिस ने फैक्ट्री में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार और एक नाबालिग को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 7 हजार रुपए की नकदी तथा एक चोरी की स्कूटी भी बरामद की है। जांच के दौरान वाहन चोरी के दो अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है।

पुलिस के अनुसार, राजगढ़ कॉलोनी निवासी नागेंद्र महतो ने अपनी फैक्ट्री में चोरी होने की शिकायत दिल्ली पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर 24 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 305/331 के तहत ई-एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया कि अज्ञात बदमाश फैक्ट्री का गेट तोड़कर अंदर घुसे और नकदी चोरी कर फरार हो गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई, मुखबिरों का नेटवर्क सक्रिय किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे आरोपियों की गतिविधियों और भागने के रास्ते का पता चला। लगातार निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने 21 वर्षीय सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 17 वर्षीय नाबालिग साथी को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर चोरी की 7 हजार रुपये की नकदी बरामद की गई।

दोनों की संलिप्तता सामने आई

जांच के दौरान पुलिस ने एक चोरी की स्कूटी भी बरामद की, जिसका संबंध गांधी नगर थाने में दर्ज वाहन चोरी के एक अन्य मामले से निकला। आगे की पूछताछ में एक और स्कूटी चोरी के मामले में भी दोनों की संलिप्तता सामने आई। पूछताछ में सलमान ने बताया कि वह स्मैक और शराब का आदी है तथा नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी, सेंधमारी और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। इस कार्रवाई को थाना गांधी नगर की टीम ने अंजाम दिया। जिसमें एसआई विकास कुमार, एचसी विवेक कुमार, एचसी राहुल चौधरी, एचसी अमन बंसल और कांस्टेबल प्रिंस शामिल थे।

दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी

कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के बदले मिजाज का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार और बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से दोपहर और शाम के समय तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

पूर्वानुमान के मुताबिक दिनभर गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि दोपहर और शाम के समय तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 1 जुलाई को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश और दोपहर एवं शाम के समय तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद 2 जुलाई से मौसम में और सुधार देखने को मिल सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार, इस दिन अधिकतम तापमान घटकर 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है, हालांकि कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

परहेज करें

3 जुलाई और 4 जुलाई को भी बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इन दोनों दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन बीच-बीच में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी गतिविधियों के सक्रिय होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे मौसम परिवर्तन का प्रभाव अब मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। इससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होगी और लोगों को भीषण गर्मी तथा उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि येलो अलर्ट के दौरान तेज हवाओं और गरज-चमक के समय अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर ढांचों के पास खड़े होने से परहेज करें।

फर्जी सांसद स्टिकर लगाकर घूम रहा युवक, दिल्ली में एसयूवी जब्त

नई दिल्ली, वेब वार्ता

राजधानी दिल्ली में सांसद का फर्जी स्टिकर और झंडा लगाकर रौब झाड़ने का मामला सामने आया है। दक्षिणी दिल्ली के लाडो सराय क्षेत्र से एक काली एसयूवी को जब्त किया गया है, जिस पर संसद का फर्जी पार्किंग स्टिकर और सांसद का झंडा लगा हुआ था। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि वाहन का उपयोग नकली पहचान के सहारे प्रभाव जमाने और जांच से बचने के लिए किया जा रहा था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला 21 जून का है। हरियाणा के मुरथल स्थित मन्नत हवेली भोजनालय में शाम करीब 5:20 बजे काले रंग की एक स्कॉर्पियो दिखाई दी, जिस पर 'पार्लियामेंट ऑफ इंडिया' का पार्किंग स्टिकर तथा सांसद का झंडा लगा हुआ था। वाहन को देखकर वहां मौजूद एक व्यक्ति को संदेह हुआ, जिसके बाद उसने संसद भवन नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद संबंधित एजेंसियों ने वाहन के बारे में जांच शुरू की। जांच में पता चला कि संबंधित वाहन संख्या के लिए संसद की ओर से कोई अधिकृत पार्किंग स्टिकर जारी नहीं किया गया था। इसके बाद शाम करीब 8:45 बजे सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करते हुए अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली पुलिस, अपराध शाखा और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने वाहन की तलाश शुरू कर दी।

जांच के दौरान वाहन के पंजीकरण विवरण के आधार पर पुलिस ने लाडो सराय स्थित प्रमोद चौधरी के आवास पर छापेमारी की। वहां संदिग्ध एसयूवी खड़ी मिली, जिस पर वही फर्जी संसद स्टिकर और झंडा लगा हुआ था। पूछताछ के दौरान प्रमोद चौधरी ने बताया कि वाहन का उपयोग उनका पुत्र देव चौधरी करता है। हालांकि, परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि उनका किसी सांसद से कोई संबंध है अथवा उन्हें इस प्रकार का स्टिकर और झंडा उपयोग करने की अनुमति प्राप्त है।

पुलिस का मानना है कि वाहन पर फर्जी पहचान चिह्न लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर प्रभाव जमाने और सुरक्षा जांच से बचने का प्रयास किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी स्टिकर और झंडा कहां से प्राप्त किया गया तथा क्या इनका पूर्व में भी किसी अन्य स्थान पर दुरुपयोग किया गया है। पुलिस आरोपित की गतिविधियों और उसके संपर्कों की भी गहन जांच कर रही है।

रांची के लिए चल रही विशेष रेलगाड़ी को विस्तार

नई दिल्ली, 30 जून (वेब वार्ता)। यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार से रांची जंक्शन के बीच चल रही विशेष रेलगाड़ी की सेवा अवधि को विस्तार दिया गया है। गाड़ी संख्या 02877 रांची जंक्शन से प्रत्येक शनिवार (25 जुलाई तक) को चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 02878 आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक रविवार (26 जुलाई तक) को रांची जंक्शन के लिए चलेगी।

आयुष्मान भारत में यकृत प्रत्यारोपण को शामिल करने की उठी मांग

नई दिल्ली,वेब वार्ता

देश में तेजी से बढ़ रहे यकृत रोगों के बीच यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के 10वें दीक्षांत समारोह में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यकृत प्रत्यारोपण को शामिल करने की मांग प्रमुखता से उठी। संस्थान के कुलाधिपति डॉ. एसके सरीन ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से इस संबंध में आग्रह किया। इस पर जेपी नड्डा ने सुझाव दिया कि इस विषय पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर मंत्रालय को भेजा जाए, ताकि इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सके।

समारोह को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश में यकृत संबंधी रोग एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैटी यकृत की समस्या अब व्यापक स्तर पर सामने आ रही है और इसके प्रति जनजागरूकता बढ़ाने में यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत नवस्नातकों से करुणा, संवेदनशीलता और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ समाज की सेवा करने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में विभिन्न अति विशिष्ट चिकित्सा, अनुसंधान तथा परिचर्या पाठ्यक्रमों के 58 विद्यार्थियों को उपाधियां, प्रमाणपत्र और पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। डॉ. सरीन ने बताया कि संस्थान में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय यकृत रोग जैव भंडार विकसित किया गया है, जिसमें 65 लाख जैविक नमूनों को संरक्षित करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त संस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चिकित्सा, कोशिका चिकित्सा इकाई, डिजिटल विकृति विज्ञान तथा अनेक उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार देखा है। उन्होंने कहा कि अति विशिष्ट चिकित्सा शिक्षा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है। समारोह के दौरान संस्थान की उपलब्धियों, अनुसंधान कार्यों तथा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित स्वस्थ यकृत अभियानों की जानकारी भी दी गई।

...बीमारियों का प्रमुख कारण बनती जा रही है

डॉ. एसके सरीन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में देश का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति फैटी यकृत की समस्या से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि यह केवल यकृत तक सीमित बीमारी नहीं है, बल्कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर तथा गुर्दा रोग जैसी अनेक असंचारी बीमारियों का प्रमुख कारण बनती जा रही है। उन्होंने समय पर जांच, जनजागरूकता और जीवनशैली में सुधार को इस चुनौती से निपटने का प्रभावी उपाय बताया। संस्थान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए डॉ. सरीन ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान संस्थान में 1.60 लाख से अधिक रोगियों का उपचार किया गया तथा 10,800 से अधिक यकृत आपात स्थितियों का सफल प्रबंधन किया गया। उन्होंने बताया कि संस्थान अब तक 1,392 सफल यकृत प्रत्यारोपण कर चुका है, जबकि बीते वर्ष 160 यकृत प्रत्यारोपण संपन्न किए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत यह संस्थान प्रदेश का एकमात्र ऐसा केंद्र है, जहां गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है। अब तक यहां 372 गुर्दा प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं, जिनमें 29 प्रतिशत लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

फेडरल रिजर्व गवर्नर को हटाने की राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश हुई नाकाम

■ वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा कानूनी झटका लगा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फेडरल रिजर्व बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को उनके पद से हटाने के उनके प्रयास को 5-4 के बहुमत से खारिज कर दिया। यह 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद पहला ऐसा मौका है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक के किसी अधिकारी को हटाने की कोशिश की हो, और सर्वोच्च अदालत ने इसे असफल कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय पीठ ने ट्रंप प्रशासन के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को हटाने की मांग की गई थी, जिसने फेड गवर्नर लिसा कुक को तत्काल बर्खास्त करने से रोका था।

अमेरिका फर्स्ट या परिवार फर्स्ट ? ट्रंप के बेटों ने कमाए 1.6 अरब डॉलर

■ वॉशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है, जिसमें उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालिया खुलासे के मुताबिक, अमेरिकी सरकार ने कजाकिस्तान के साथ एक ऐसी बड़ी डील की है, जिससे सीधे तौर पर ट्रंप के बेटों और उनके वाणिज्य मंत्री के परिवार को अरबों डॉलर का वित्तीय फायदा होने जा रहा है। यह मामला अमेरिका में नैतिक और हितों के टकराव को लेकर बहस छेड़ रहा है। यह खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसके अनुसार अमेरिका ने कजाकिस्तान के साथ दुनिया के सबसे बड़े दुर्लभ खनिज टंगस्टन के भंडार को विकसित करने के लिए 1.6 अरब डॉलर (लगभग 13,500 करोड़ रुपये) की सरकारी डील की है।

नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री धामी ने की बैठक

सड़क अवसंरचना के लिए उत्तराखंड को सात हजार करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 30 जून (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक कर उत्तराखण्ड से संबंधित सड़क एवं अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया। इस बैठक में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की सड़क अवसंरचना के लिए सात हजार करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक व रणनीतिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन व आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सुदृढ़ और आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय का अनुरोध किया।

सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट कर मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार को लगभग 750 करोड़ लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति पर सहमति दे दी है। इसके साथ ही एनओएच के अंतर्गत पांच प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग रुपए 2966 करोड़ है। इनमें श्रीनगर बाईपास का पीएमसी, पुरकाजीझलक्सरझहरिद्वार मार्ग की चार-लेनिंग, लोहाघाट व पिथौरागढ़ बाईपास एलाइनमेंट, मझोला से खटीमा के आबादी भाग में चार-लेन विस्तार व रामनगरझरानीखेत (मोहन) मार्ग का सुदृढ़ीकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की रुपए 530.11 करोड़ की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र अवमुक्त किए जाने तथा का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने आगामी अर्धकुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे यातायात दबाव में कमी आएगी तथा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार बाईपास परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था सुगम हो सके तथा स्थानीय जनता को जाम की समस्या से राहत मिले। दोनों ही प्रस्तावों को सहमति दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि नेशनल हाईवे के माध्यम से अन्य मार्गों के संयोजन के लिए कुछ परियोजनाओं के लिए लगभग 3 हजार करोड़ की सैद्धांतिक सहमति देने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण के लिए लगभग रुपए 300 करोड़ की परियोजना पर चर्चा और सैद्धान्तिक सहमति बन गई। इसके अलावा राज्य में आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्यों के लिए डीपीआर तैयार किए जाने के लिए अनुबंध करने का अनुरोध किया, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी एवं वैज्ञानिक समाधान सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन से संबंधित लंबित मामलों, विशेषकर ऋषिकेशझगंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिनाझतेखलाझनेतालाझगरमपानी खंड की डीपीआर तथा जोशीमठ बाईपास मार्ग के संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत कम दरों पर प्राप्त निविदाओं के मामलों में अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया जाए, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं स्लोप ट्रीटमेंट कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से इन सभी परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड में सड़क संपर्क एवं आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी।

एआई से नुकसान पर नजर रखने लॉन्च किया अर्ली वॉर्निंग ट्रैकर

कैलिफोर्निया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण बेरोजगारी फैलने के डर को कम करने और भविष्य के लिए तैयार रहने के उद्देश्य से अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो एआई की वजह से होने वाली नौकरियों के नुकसान पर बारीकी से नजर रखता है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम के कार्यालय के अनुसार, इस ट्रैकर का मुख्य उद्देश्य एआई के कारण बड़े पैमाने पर होने वाली नौकरियों की हानि के लिए एक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (समय से पहले चेतावनी देने वाला सिस्टम) के तौर पर काम करना है। यह प्रणाली सरकार को यह तय करने में मदद करेगी कि कहां सबसे ज्यादा दखल देने या सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। यह ट्रैकर कैसे काम करेगा, यह जानने के लिए कैलिफोर्निया सरकार ने कैलिफोर्निया एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ-साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कैलिफोर्निया पॉलिसी लैब के साथ मिलकर काम किया है।

जानकारी के अनुसार, वे ट्रैकर में आंकड़े लाने के लिए एकीकृत बेरोजगारी बीमा दावों के डेटा का उपयोग करते हैं, जिसे एआई एक्सपोजर उपायों के साथ जोड़ा गया है। यह डेटा मासिक रूप से अपडेट किया जाएगा, और कोई भी नागरिक इस डेटा को ऑनलाइन देख सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस ट्रैकर को ऐसे समय में बनाया गया है जब अधिकारियों पर एआई की वजह से नौकरियों के नुकसान के मामले में अधिक सक्रिय होने का दबाव बढ़ रहा था। यह ट्रैकर यूजर्स को शिक्षा, लिंग, उम्र, जातीयता और नस्ल जैसे अलग-अलग वर्गों के आधार पर एआई के संभावित असर को देखने की सुविधा भी देगा, जिससे यह पता चल सके कि कौन से समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।

हालांकि, इस ट्रैकर के डेटा का अध्ययन करने वाले कुछ शोधकताओं का यह भी कहना है कि इसे पूरी तरह पक्की गाइड नहीं माना जा सकता, क्योंकि एआई के प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। अगर इस तरह का सिस्टम पूरी दुनिया में फैल जाए तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगर अन्य देश भी एआई की वजह से नौकरी जाने पर नजर रखने वाले ऐसे ही सिस्टम अपनाते हैं, तो हम देखेंगे कि सरकारें बड़े पैमाने पर छंटनी जैसी समस्या के आम लोगों पर असर डालने से पहले ही तेजी से कदम उठाएंगी। इसके अलावा, एआई के नियम-कानून काफी हद तक डेटा पर आधारित हो सकते हैं, और असल में यही आज की जरूरत भी है ताकि नीतियां यथार्थवादी और प्रभावी हों।

यह प्रणाली बड़े पैमाने पर छंटनी करने वाली कंपनियों पर भी नैतिक और नियामक दबाव डालेगी, क्योंकि उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। इससे लोगों को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जिससे वे यह तय कर पाएंगे कि उन्हें अपने कौशल को अद्यतन करने या अपने काम या करियर में क्या बदलाव करने की जरूरत है।

महाराष्ट्र में बढ़ गई सियासी गरमाहट

पीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के नाम का किया ऐलान!

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अप्रत्याशित बयान सामने आया है, जहां शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हितैषी हैं और यदि वे प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे। शिरडी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, अगर वह (फडणवीस) सोचते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं, तो बता दूं कि मैं उनका हितैषी हूं। मैं उनके मन की बात कर रहा हूं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राज्य में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों का समर्थन हासिल किया है।

ठाकरे ने दावा किया कि ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे 2029 में फडणवीस प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो सकें। उन्होंने स्पष्ट किया, अगर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो मेरी पार्टी उसका समर्थन क्यों नहीं करेगी। हालांकि, ठाकरे ने अपने बयान में एक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करते हैं तो यह भाजपा में उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा होगा। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, अगर फडणवीस यह घोषणा करते हैं कि वह प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वह अपनी पार्टी में बने भी रह पाएंगे?

शिरडी में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने दलबदलू सांसदों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में लोकसभा सदस्य भाऊसाहेब वाकचौरे गए हैं, वह पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वाकचौरे हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं और शिरडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठाकरे ने यह भी बताया कि शिरडी मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने साईं बाबा से फडणवीस की कुर्सी की रक्षा करने की प्रार्थना की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के पीछे उनका हाथ था। इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके पास राज्य के 14 करोड़ लोगों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है, इसलिए कोई भी उनके पंख नहीं काट सकता। मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व सहयोगी और अब प्रतिद्वंद्वी उद्धव ठाकरे के साथ मुंबई से नागपुर के लिए एक ही विमान में यात्रा करने के बाद शुरू हुई राजनीतिक अटकलों को भी खारिज कर दिया और इसे महज एक इत्तेफाक बताया था।

रहस्यमय ग्रहों-यूरेनस और नेपच्यून बर्फ का गोला नहीं खोलता हुआ मैग्मा छिपा है

वैज्ञानिक अब दोनों ग्रहों की अंदरूनी बनावट को नए सिरे से समझने में जुटे

नई दिल्ली। सौर मंडल के दो सबसे रहस्यमय ग्रहों-यूरेनस और नेपच्यून को लेकर वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अब तक पूरी दुनिया इन दोनों ग्रहों को आइस जायंट यानी बर्फ के गोले मानती थी, लेकिन एक नई रिसर्च ने इस पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

रिसर्चर्स ने कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से एक नया खुलासा किया है। इस स्टडी के मुताबिक इन दोनों ग्रहों के अंदर बर्फ नहीं है। वहां बर्फ के बजाय खौलते हुए मैग्मा का एक बहुत बड़ा महासागर छिपा है। वैज्ञानिक अब इन दोनों ग्रहों की अंदरूनी बनावट को नए सिरे से समझने की कोशिश में जुट गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासा के वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने साल 1986 और 1989 में इन ग्रहों के पास से उड़ान भरी थी। तभी से वैज्ञानिक इन्हें बर्फ के ग्रह मानते आ रहे हैं। पुरानी थ्योरी कहती थी कि इनके हाइड्रोजन और हीलियम वाले एटमॉस्फेयर के नीचे बर्फ की एक मोटी परत है। लेकिन इन ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड और हीट डिस्ट्रीब्यूशन ने हमेशा वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा था। अब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिम्युलेशन के जरिए असली सच का पता लगाया है। रिसर्चर्स ने पाया कि इन ग्रहों का अंदरूनी हिस्सा वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे। यह स्टडी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश होने के लिए भेजी गई है। इसने वैज्ञानिकों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

इस नए मॉडल ने यूरेनस और नेपच्यून की अंदरूनी परतों का एक नया नक्शा तैयार किया है।

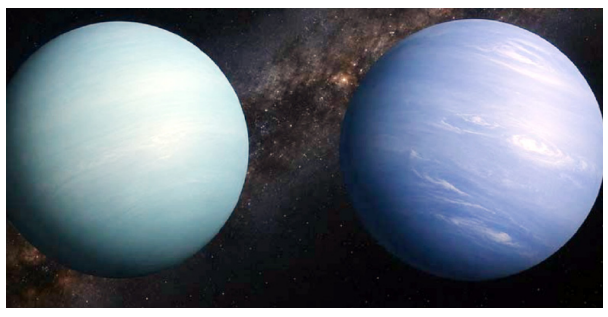

सबसे ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर है जो गर्मी को स्पेस में भेजता है। इसके ठीक नीचे एक बहुत ही अजीब बाउंड्री लेयर मौजूद है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मैग्नीशियम भी शामिल है। इतना ही नहीं वहां सिलिकॉन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस परत के नीचे मैग्मा का समंदर है। यह मैग्मा मुख्य रूप से सिलिकेट और आयरन से बना हुआ है. इस वजह से ये ग्रह बर्फ के गोले की जगह मैग्मा वर्ल्ड्स नजर आते हैं।

क्या सौर मंडल के बाहर छिपे दूसरे ग्रहों का रहस्य भी अब खुल जाएगा?

हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह नहीं था इसलिए इनके बनने की कहानी हमेशा एक रहस्य रही है। अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सब-नेपच्यून ग्रहों की केमिस्ट्री भी इन मैग्मा ओशन्स से प्रभावित हो सकती है. इससे ब्रह्मांड के कई दूसरे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वॉयजर 2 के बाद से आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट इन दोनों ग्रहों के पास नहीं गया है। लेकिन अब वैज्ञानिक वहां वापस जाने के लिए नए मिशन डिजायन कर रहे हैं। इसमें यूरेनस ऑर्बिटर एंड प्रोब और नेपच्यून ओडिसी जैसे नाम शामिल हैं। यूरेनस ऑर्बिटर प्रोब सीधे ग्रह के एटमॉस्फेयर में गोता लगाएगा। यह मिशन इन ग्रहों के चक्कर लगाते हुए इनके चंद्रमाओं का भी बारीकी से अध्ययन करेगा। इन फ्यूचर मिशन्स से मिलने वाला डेटा ही यह साफ करेगा कि वहां सच में मैग्मा का समंदर है या नहीं। तब तक के लिए साइंस की दुनिया में यह बहस लगातार गर्म रहने वाली है।

संसद में दो-तिहाई बहुमत की चुनौती और सीटों के विस्तार पर सरकार का मंथन

संविधान संशोधन बिल को लेकर फिर शुरू हुई चर्चा

नई दिल्ली। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर विधेयक लाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अटकलें तेज हैं कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) इसे फिर से पेश करने का प्रयास कर सकता है।

ऐसे किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा झ में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, और सीटों के लिहाज से भाजपा सबसे बड़ा दल होने के बावजूद एनडीए इस महत्वपूर्ण आंकड़े से काफी दूर है।

इस बीच, सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कई नए फॉमूर्लों पर विचार कर रही है, विशेष रूप से महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए। एक प्रस्ताव यह है कि सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए, ताकि दक्षिणी राज्यों की उन चिंताओं को दूर किया जा सके कि आबादी के आधार पर परिसीमन से लोकसभा में उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी।

ये है लोकसभा का समीकरण

लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से वर्तमान में तीन सीटें (बशीरहाट, शिलॉन्ग और नौगांव) खाली हैं, जिससे प्रभावी संख्या 540 रह जाती है। ऐसे में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 360 होता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए की सीटें 293 थीं, जो हाल ही में कुछ अन्य सांसदों के समर्थन से बढ़कर 319 हो गई हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना (यूबीटी) के 6 बागी सांसदों का समर्थन शामिल है। लोकसभा में भाजपा के पास 240 सीटें हैं, जबकि विपक्षी कांग्रेस के पास 98 सीटें हैं। अन्य प्रमुख दलों में समाजवादी पार्टी (37), तृणमूल कांग्रेस (28), द्रमुक (22), तेलुगु देशम पार्टी (16), जनता दल यूनाइटेड (12), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) (8), और शिवसेना (शिंदे गुट) (7) शामिल हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यदि द्रमुक मतदान से दूर रहती है, तो दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा घटकर 342 पर आ जाएगा। अप्रैल में जब पहले संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया था, तब एनडीए को 298 सदस्यों का समर्थन मिला था, जो पारित कराने के लिए पर्याप्त नहीं था।

व्यवस्था का अनुरोध किया है

नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव है, जबकि लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि अभी की जा रही जनगणना के आंकड़े आने बाकी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि महिला आरक्षण कानून 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू हो सके, जिसके लिए मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मॉनसून सत्र से पहले तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में हुई बगावत के मामलों पर भी फैसला करेंगे, जबकि द्रमुक ने तमिलनाडु में कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था का अनुरोध किया है।

उच्च सदन 164 सीटों की आवश्यकता

उच्च सदन, राज्यसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 242 है। यहां दो-तिहाई बहुमत के लिए एनडीए को 164 सीटों की आवश्यकता है। लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन थोड़ा मजबूत है, लेकिन आवश्यक आंकड़े से अभी भी दूर है। राज्यसभा में भाजपा के पास 114 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 30, तृणमूल कांग्रेस के पास 10, द्रमुक के पास 8 और बीजू जनता दल के पास 5 सीटें हैं। इसके अलावा, अन्नाद्रमुक, जदयू, राकांपा, समाजवादी पार्टी और तेदेपा के पास 4-4 सांसद हैं, जबकि 7 नामित और 4 निर्दलीय या अन्य सदस्य हैं।

रूसी आर-37एम का 190 किमी से अचूक निशाना, भारत को चीन पर देगी बड़ी बढ़त

मॉस्को। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूसी वायुसेना ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसका भारत के लिए सामरिक महत्व है। रूसी सुखोई एसयू-35एस लड़ाकू विमान ने अपनी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल आर-37एम का प्रयोग कर लगभग 190 किलोमीटर की असाधारण दूरी से एक यूक्रेनी एमआईजी-29 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज (बीवीआर) एयर-टू-एयर मिसाइल की क्षमता में एक नया रिकॉर्ड है, जिसकी रफ्तार मैक 5 से भी अधिक है। यूक्रेन ने पोलटावा ओब्लास्ट के ऊपर 26-27 जून की रात हुई घटना में अपने एमआईजी-29 के गिरने की पुष्टि की है, हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। यह रूस की किल चेन और नेटवर्क-सेंट्रिक हवाई युद्ध की क्षमताओं का प्रदर्शन है, जो दूर से मिसाइल दागने पर आधारित है। भारत के लिए यह खबर इसलिए उत्साहवर्धक है क्योंकि वह इस बेहद प्रभावी मिसाइल को रूस से खरीदने वाला है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, भारत ने करीब 1.2 अरब डॉलर (करीब 10,000 करोड़ रुपये) के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके तहत लगभग 300 आर-37एम अल्ट्रा-लॉन्ग-रेंज मिसाइलें भारतीय वायुसेना को मिलेंगी। इन मिसाइलों को अगले 12 से 18 महीनों के भीतर मिलना शुरू होगा और इन्हें मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के एसयू-30एमकेआई फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा, जिससे उनकी मारक क्षमता में भारी इजाफा होगा।

अरुणाचल में गांव वाले बोले

चीनी सेना निजी जमीन पर कब्जा कर रही

सुबनसिरी। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा घुसपैठ और स्थानीय लोगों की पैतृक जमीन पर कब्जा करने के दावों ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। सीमावर्ती इलाके में सक्रिय एक स्थानीय सामुदायिक संगठन नाह वेलफेयर सोसाइटी (एनडब्ल्यूएस) के इन गंभीर आरोपों के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार इन दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन करेगी। हालांकि, इन दावों के सामने आने के तुरंत बाद भारतीय सेना ने इन्हें गलत और आधारहीन बताते हुए इनका खंडन किया है। नाह वेलफेयर सोसाइटी ने हाल ही में जिले के डिप्टी कमिश्नर को लिखे एक पत्र में भारत-चीन सीमा पर चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का दावा है कि चीनी सरकार तेजी से अपनी सीमा का विस्तार कर रही है और भारतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर रही है। पत्र में कहा गया है कि चीन ने स्थानीय लोगों की पैतृक जमीन पर कई जगहों पर मिलिट्री कैंप स्थापित कर लिए हैं, और इसके अलावा वहां सड़कों तथा पुलों का भी निर्माण किया गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, जिन इलाकों पर चीन कब्जा कर रहा है, वे उनके पारंपरिक शिकार के मैदान रहे हैं, जहां कुछ साल पहले तक वे बेरोकटोक घूमते थे और जंगलों से उत्पाद इकट्ठा करते थे। सोसाइटी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके मवेशी जहां चरने जाते थे, वे इलाके अब पूरी तरह से चीनी सेना के कब्जे में जा चुके हैं। दावों के मुताबिक, पिछले 10 से 15 सालों में सीमा पर चीन की इन अतिक्रमण वाली गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है। संगठन ने अपने पत्र में लिखा, ताकसिंग इलाके में चीनी सेना जिस मंशा और रफ्तार से काम कर रही है, वह हमारे लिए बेहद खतरनाक और गंभीर चिंता का विषय है। हम हर दिन इंच-दर-इंच अपनी जमीन उनके हाथों गंवा रहे हैं। इन दावों का संज्ञान लेते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है। गृह मंत्री मामा नटुंग ने स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट जिला प्रशासन, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और पंचायत समितियों के निष्कर्षों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा, फिलहाल ये सिर्फ दावे हैं।

संत कबीर का संदेश आज भी समाज और राष्ट्र के लिए पथप्रदर्शक : थावरचंद गहलोत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत राजधानी रायपुर के सोनपैरी स्थित सद्गुरु कबीर आश्रम में कबीर जयंती के अवसर पर आयोजित संत कबीर महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गुरु असंग देव का आशीर्वाद लेकर प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने आश्रम परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। गुरु असंग

देव ने कहा कि संत कबीर ने समाज से पाखंड, कुरीतियों और आडंबर को समाप्त करने के लिए अवतार लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समाज में आपसी प्रेम तथा संवाद कम होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने सेवा, परमार्थ, गौसेवा, वृक्षारोपण और ग्राम विकास को जीवन का आधार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सेवा से ही सच्चा सुख और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। गुरु असंग देव ने कहा कि एक समय नक्सलवाद के कारण जिन क्षेत्रों में जाना कठिन था, वहां अब शांति स्थापित हो चुकी है और विकास की गंगा बह रही है। लाखों गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं और प्रदेश विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि संत कबीर ने सत्य, समरसता, मानव सेवा और सद्भाव का जो संदेश दिया, वह आज भी पूरे समाज और राष्ट्र के लिए पथप्रदर्शक है। उन्होंने जात-पात, ऊंच-नीच और आडंबर से ऊपर उठकर मानव मात्र को प्रेम, सत्य और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज जब समाज सामाजिक विभाजन और नैतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब संत कबीर की वाणी पहले से अधिक प्रासंगिक है। राज्यपाल ने सोनपैरी कबीर आश्रम द्वारा शिक्षा, गौसेवा, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आश्रम राष्ट्र निर्माण की चेतना को सशक्त बनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ संत कबीर की तपोभूमि और उनके अनुयायियों को पावन धरती है। उन्होंने कहा कि उनका बचपन कबीरपंथी समाज के बीच बीता है और संत कबीर की वाणी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत कबीर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज में फैली कुरीतियों, छुआछूत, जाति-पांति और आडंबर के विरुद्ध जनजागरण में समर्पित किया। उन्होंने निर्भीक होकर सत्य का साथ दिया और अपने सरल किंतु प्रभावशाली विचारों से समाज को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज भी उनकी शिक्षाएं समाज में प्रेम, भाईचारे और समरसता की प्रेरणा देती हैं।

ताजा खबर
संक्षिप्त

मुख्यमंत्री साय से कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए राज्यपाल श्री गहलोत का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर की समृद्ध कला एवं सांस्कृतिक विरासत बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर आत्मीय चर्चा हुई।

सरस्वती साइकिल योजना से वैष्णवी के सपनों को मिली नई उड़ान'

रायपुर। सरस्वती साइकिल वितरण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है, जिसके तहत हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूल तक आवागमन सुगम बनाने के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों से सुरक्षित और समय पर स्कूल पहुँचाने में मदद करना और ड्रॉप-आउट दर को कम करना है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक पहल साबित हो रही है। सूरजपुर जिले के शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरजपुर की छात्रा वैष्णवी कसेरा को निःशुल्क साइकिल प्रदान की गई, जिससे उसके शिक्षा के सपनों को नई उड़ान मिली है।

रथयात्रा पर गोंदिया-पुरी के बीच चलेगी रथयात्रा स्पेशल ट्रेन

रायपुर. रथयात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया-पुरी-गोंदिया के बीच रथयात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 08801/08802 का संचालन जुलाई माह में चार-चार फेरों के लिए किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ और ओडिशा के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गोंदिया-पुरी रथयात्रा स्पेशल (08801) का संचालन 2, 9, 16 और 29 जुलाई 2026 को होगा। यह ट्रेन गोंदिया से दोपहर 1:30 बजे रवाना होकर दुर्ग शाम 3:58 बजे और रायपुर शाम 5:10 बजे पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 10 बजे यह पुरी पहुंचेगी। वापसी में पुरी-गोंदिया रथयात्रा स्पेशल (08802) 3, 10, 17 और 30 जुलाई 2026 को पुरी से दोपहर 1 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन तड़के 3:10 बजे रायपुर, 4:28 बजे दुर्ग होते हुए सुबह 7 बजे गोंदिया पहुंचेगी।

विशेष ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटाबांजी, टिटलागढ़, बलांगीर, बरगढ़ रोड, संबलपुर, अंगुल, तालचेर रोड, ढेंकानाल, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड सहित प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। दोनों दिशाओं में निर्धारित समयानुसार यह ट्रेन रुकेगी। रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन में 20 आईसीएफ कोच लगाए हैं, जिनमें दिव्यांग अनुकूल सह गार्ड कोच, 10 शयनयान, 3 थर्ड एसी और 2 सेकेंड एसी कोच शामिल हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय सम्मेलन में की छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक मॉडल की सराहना

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल मटेरियल बैंक मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सराहना मिली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत विकसित इस मॉडल की प्रशंसा करते हुए इसे ग्रामीण आवास निर्माण को गति देने वाला प्रभावी नवाचार बताया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने किया। छत्तीसगढ़ में विकसित मटेरियल बैंक मॉडल का संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा डीलर दीदी के रूप में किया जा रहा है।

इसके माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को निर्माण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आवास निर्माण कार्य अधिक सुगम, तेज और किफायती हुआ है। इस पहल से स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और 10,000 से अधिक दीदियां लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ी हैं। इस मॉडल को महिला

सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में एक प्रभावी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया।केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार और प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ने के लिए आरसेटी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में आरसेटी के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष में देश में सर्वाधिक राज मिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया है ।उन्होंने इन प्रयासों को अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक बताया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण विकास, कौशल उन्नयन, स्वरोजगार संवर्धन और गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह सराहना प्रदेश के जनकल्याणकारी कार्यों, नवाचारों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है तथा इससे राज्य को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की सराहना: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने की मटेरियल बैंक मॉडल की तारीफ

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक मॉडल की सराहना की। उन्होंने इसे हितग्राहियों के लिए बेहद उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल बताया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मटेरियल बैंक मॉडल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को एक ही स्थान पर घर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहा है। इससे निर्माण सामग्री जुटाने में होने वाली परेशानी कम हुई है और मकान निर्माण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुगम, तेज और किफायती बनी है। उन्होंन कहा, मटेरियल बैंक के जरिए हितग्राहियों को सीमेंट, सरिया, ईंट, गिट्टी, रेत सहित अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है।

बाल साहित्य और नई शिक्षा नीति को मिलेगा नया आयाम: केदार कश्यप

मोर अंगना के शोर साझा बाल काव्य संग्रह का हुआ विमोचन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज राजधानी रायपुर के वृंदावन भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने साझा बाल काव्य संग्रह मोर अंगना के शोर का विमोचन किया और सभी संबंधित रचनाकारों व शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास शिक्षा, संस्कार और साहित्य के माध्यम से ही संभव है। बाल साहित्य हमारी नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने का काम करता है। मंत्री श्री कश्यप ने पुस्तक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोर अंगना के शोर केवल कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह बच्चों की कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों और भाषा कौशल को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है।

यह अभिनव प्रयास नई शिक्षा नीति (हृश्वक) और बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (स्नरू) उद्देश्यों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। तकनीक और साहित्य का अनूठा संगमर- क्यूआर कोड आधारित नवाचार इस बाल काव्य संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसमें शामिल तकनीकी नवाचार है। पुस्तक में प्रत्येक कविता के साथ एक क्यूआर (त्तक्र) कोड जोड़ा गया है। इस पहल की सराहना करते हुए वन मंत्री ने कहा कि इससे बच्चे केवल कविताओं को पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें सुनकर भी सीख सकेंगे। यह साहित्य और तकनीक का एक बेहतरीन समन्वय है जो शिक्षा को अधिक रोचक, सरल और समावेशी बनाएगा। उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि यह अनूठी पहल दिव्यांग बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, जिससे वे भी समान रूप से सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। मंत्री श्री कश्यप ने पुस्तक के संपादक श्री वीरेंद्र कुमार साहू, सभी लेखकों, शिक्षकों एवं सहयोगियों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि जब शिक्षा, साहित्य और समाज मिलकर कार्य करते हैं, तब राष्ट्र निर्माण की दिशा और अधिक मजबूत होती है।

सहकारिता आंदोलन को जनभागीदारी का महाअभियान बना रही है साय सरकार- केदार कश्यप

गांव-गांव तक सहकारिता को मजबूत कर रही सरकार

रायपुर। सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता सप्ताह के शुभारंभ आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, रायपुर में सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर विकास करने की एक मजबूत सोच है। सरकार का मुख्य लक्ष्य सहकारिता को एक जनआंदोलन बनाकर प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद, केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में सहकारिता क्षेत्र को एक नई और मजबूत पहचान मिली है। पिछले पांच वर्षों में सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारिता को गांव-गांव तक मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्राथमिक कृषि साख समितियों को सशक्त बनाया जा रहा है, किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि साथ मिलकर विकास ही सहकारिता का मूल मंत्र है और इसी भावना से आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव होगा। उन्होंने सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी सेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आग्रह किया, ताकि सहकारी व्यवस्था पर जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने आगे कहा कि यह सहकारिता सप्ताह केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सहकारिता की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का महाअभियान है।

सप्ताहभर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित वामनराव बलिराम लाखे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर की। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष श्री निरंजन सिन्हा, उपाध्यक्ष श्री अभिनेष कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे।

भाजपा महिला मोर्चा की नई जिला प्रभारियों को मुख्यमंत्री साय ने दी शुभकामनाएं

राष्ट्रहित की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, छत्तीसगढ़ में नई नियुक्तियों का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रदेश संगठन द्वारा नव-नियुक्त जिला प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की सूची जारी की गई है। इस महत्वपूर्ण सांगठनिक बदलाव पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, छत्तीसगढ़ की नव-नियुक्त जिला प्रभारी एवं सह-प्रभारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि आप सभी संगठन की सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। आप सभी के सफल एवं उज्ज्वल कार्यकाल के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा जशपुर

रायपुर। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और विविध पर्यटन स्थलों के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। हरी-भरी पहाड़ियां, घने साल के जंगल, कल-कल बहते झरने, स्वच्छ नदी-नाले और शांत वातावरण जशपुर को प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। महानगरों की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं।

उद्यानिकी विभाग की योजना से बदली कमार कृषक की तकदीर

रायपुर। उद्यानिकी विभाग की योजना से बदली कमार कृषक की तकदीरखीरे की व्यावसायिक खेती एक बेहद लाभदायक व्यवसाय है, जो 45 से 50 दिनों में पैदावार देना शुरू कर देता है। व्यावसायिक खेती में खीरे को जमीन पर फैलाने के बजाय मचान और तारों का सहारा देकर ऊपर चढ़ाना चाहिए। इससे फल जमीन के संपर्क में नहीं आते, गलते नहीं हैं और उनका आकार, रंग और चमक शानदार रहती है, जिससे बाजार में बेहतरीन भाव मिलता है। बुवाई के 45-50 दिनों बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। मचान विधि से एक एकड़ में लगभग 30 से 45 क्विंटल तक उपज प्राप्त हो जाती है।

सीमित संसाधनों और पारंपरिक खेती के दौर में यदि सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का साथ मिले, तो खेती कैसे फायदे का सौदा बन सकती है, इसे धमतरी जिले के एक प्रगतिशील किसान ने सच कर दिखाया है। जिला धमतरी के विकासखंड नगरी के अंतर्गत ग्राम सेलबहरा के विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार समुदाय) के कृषक श्री खीमांशु गजेसिंग आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं।

श्री गजेसिंग के पास कुल 10 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें से

उन्होंने इस वर्ष 4 एकड़ क्षेत्र में खीरे की व्यावसायिक खेती की। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के नियमित संपर्क और तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने उन्नत खेती की तकनीक, गुणवत्तायुक्त बीजों का चयन, संतुलित पोषण प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई और पौध संरक्षण जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया।

पहले पारंपरिक ढर्रे पर खेती करने के कारण श्री गजेसिंग के लिए कृषि की लागत निकालना भी एक बड़ी चुनौती थी और आय बेहद सीमित थी। लेकिन आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के बाद पासा पलट गया। वैज्ञानिक तरीके से की गई इस खेती के कारण खीरे की फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ है। स्थानीय बाजारों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी उनके खीरे की भारी मांग है। उपज का सही और उचित मूल्य मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए श्री खीमांशु गजेसिंग ने बताया कि विभागीय अधिकारियों के तकनीकी सुझावों और शासकीय योजनाओं के सहयोग से मुझे खेती को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला।

सरस्वती साइकिल योजना से वैष्णवी के सपनों को मिली नई उड़ान

रायपुर। सरस्वती साइकिल वितरण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है, जिसके तहत हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूल तक आवागमन सुगम बनाने के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों से सुरक्षित और समय पर स्कूल पहुँचाने में मदद करना और ड्रॉप-आउट दर को कम करना है।

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक पहल साबित हो रही है। सूरजपुर जिले के शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरजपुर की छात्रा वैष्णवी कसेरा को निःशुल्क साइकिल प्रदान की गई, जिससे उसके शिक्षा के सपनों को नई उड़ान मिली है। बाजारपारा निवासी वैष्णवी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि पहले वह प्रतिदिन पैदल विद्यालय आती-जाती थी, जिससे समय के साथ-साथ पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता था। अब शासन से निःशुल्क साइकिल मिलने के बाद विद्यालय पहुँचना आसान हो जाएगा और वह नियमित रूप से अध्ययन कर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अब मेरे सपनों को नया पंख मिल गया है। पहले पैदल विद्यालय आती थी, अब साइकिल से विद्यालय जाऊंगी और मन लगाकर पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी।

महत्वपूर्ण ख़बर

वैभव की प्रतिभा पर संदेह नहीं पर उन्हें भी तय प्रक्रिया से गुजरना होगा : डोएशे

- मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा है कि 15 साल के उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवशी एक बेहतरीन प्रतिभा हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार नजर आते है। डोएशे के अनुसार इसके बाद भी वैभव को टीम में जगह मिलने से पहले उसी तय प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे अन्य खिलाड़ी गुजरते है।

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से ठीक पहले वैभव को लेकर दिया गया डोएशे का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई दो मैचों की टी20 श्रृंखला में वैभव को अंतिम ग्यारह में जगह नहीं मिली। वहीं भारतीय टीम को दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से ही मांग की जा रही है कि वैभव अभी फार्म में हैं और उन्हें टीम में डेब्यू का अवसर मिले।

इसी को लकर डोएशे ने कहा कि हमें उसकी प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं । साथ ही कहा कि कि टीम में कुछ स्थापित और हाल ही में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी हैं जिन्हें बाहर नहीं किया जा सकता है।

महिला क्रिकेट को सभी विभागों में सुधार करना होगा: मजूमदार

लंदन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा है कि टीम को अभी खेल के तीनों विभागों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार की जरुरत है। अमोल के अनुसार टीम टी20 विश्वकप में इन सभी क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन नहीं कर पारी जिसके कारण ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही कहा कि टीम का सामूहिक प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जिसकी ऐसे बड़े टूनार्मेंट में उम्मीद की जाती है। मजूमदार ने भविष्य की रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें अपनी रणनीति और अपने टी20 खेल पर नए सिरे से विचार करना होगा। हमें गहराई से यह तय करने की जरूरत है कि भविष्य में हम किस संयोजन के साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं। इससे साफ है कि अब टीम में बदलाव होने तय है।

अपनी रणनीति पर भी दोबारा विचार करना होगा

कोच के अनुसार पूरे टूनार्मेंट में टीम की कमजोरियां सामने आई हैं।1 उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ खास बातों पर ध्यान देना हो, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा हमें बल्लेबाजी में भी थोड़ा और आक्रामक होना होगा।

भारत ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई

ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन-दक्षिण अफ्रीकी टीम की सीट भी पक्की

दुबई। ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड के प्रदर्शन के चलते) ने लॉस एंजलस 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए महिला टी-20 विश्व कप 2026 में अपने प्रदर्शनों के चलते प्रवेश कर लिया है। लॉस एंजलस 28 ओलंपिक्स में महिलाओं के इवेंट में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी। इन चार टीमों ने क्रमशः ओसनिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले योग्य फिनिशर के रूप में अपनी जगह पक्की की। टी-20 विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमों में से एक वेस्टइंडीज़, देशों के समूह के तौर पर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आईओसी की नेशनल ओलंपिक कमेटी के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। पुरुष टीमों के लिए चार जगहों का निर्धारण आईसीसी टी-20 रैंङ्कषकग के आधार पर होगा।

रैंङ्कषकग में 31 दिसंबर, 2026 तक अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओसनिया से सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाली योग्य टीमें ओलंपिक्स में प्रवेश पाएंगी। अमरीका बतौर मेज़बान दोनों इवेंट के लिए क्वॉलिफाई करने के योग्य है, लेकिन उन्हें 30 जून से लेकर 31 दिसंबर, 2026 की क्वॉलिफिकेशन की अवधि तक दोनों टी20 रैंङ्कषकग में शीर्ष 15 में रहना होगा। अमरीका की पुरुष टीम 13वें स्थान पर है इसलिए उनके प्रवेश करने की संभावना प्रबल है। इस समय अमरीका की महिला टीम 20वें स्थान पर है। अगर वह इस मापदंड पर खरी नहीं उतर पाती है, तो पहली मार्च, 2027 तक किसी भी महाद्वीप से, ओलंपिक्स में प्रवेश न पाने वाली टीमों में से टी20 रैंङ्कषकग में सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाली टीम को प्रवेश मिल जाएगा।

फुटबॉल पर भारी निवेश के बाद भी विश्वकप में प्रभावित नहीं कर पायीं कतर और सऊदी अरब

मियामी। फीफा विश्व में सऊदी अरब और कतर की टीम का प्रदर्शन बेहद रखा रहा और ये दोनो ही किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ पायीं जबकि इन देशों ने फुटबॉल के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मोटी रकम खर्च की थी। वहीं आर्थिक बदहाली से जूझ रही अफ्रीकी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इससे ये साबित हो गया है कि है कि खेल में मोटी रकम का निवेश करना सफलता की गारंटी नहीं बन सकता। धनी देशों सऊदी अरब और कतर ने पिछले कुछ साल में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे पर काफी निवेश किया था। उसके क्लबों ने पिछले कुछ वर्षों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जैसे स्टार खिलाड़ियों को अपने क्लबों से जोड़ा पर इसके बाद भी इनकी टीमों को विश्व कप में शर्मनाक हार के साथ टूनार्मेंट से बाहर होना पड़ा है। इसके विपरीत, बेहद सीमित संसाधनों वाले अफ्रीकी देशों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का हैरान कर दिया है।

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में विराट की वापसी के बाद ईशान नंबर 4 पर बल्लेबाजी करें : रायुडू

हैदराबाद। पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायुडू ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में विराट कोहली की वापसी को देखते हुए बल्लेबाज ईशान को चौथे नंबर पर उतारा जाना चाहिये। रायुडू के अनुसार ईशान बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिससे ईशान स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

रायुडू ने ईशान किशन के हाला के अच्छे प्रदर्शन की तारीफ की और कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी थी। धर्मशाला में 34 रन और लखनऊ में 125 रन की अपनी पारियों से इस बल्लेबाज ने अपने को साबित किया है। रायुडू के विश्लेषण के मुताबिक, विराट कोहली के नंबर-3 पर लौटने के बाद, ईशान के लिए नंबर-4 सबसे उपयुक्त स्थान होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नंबर-4 पर ईशान किशन और नंबर-5 पर श्रेयस अय्यर की जोड़ी भारत के मध्यक्रम को बेहद मजबूत और स्थिर बना सकती है।

रायुडू ने विराट कोहली की मानसिक दृढ़ता और फिटनेस की जमकर तारीफ की। रायुडू ने कहा कि विराट अपनी तैयारी, फिटनेस और प्रक्रिया को लेकर बेहद अनुशासित हैं। उन्हें हमेशा पता होता है कि खराब दौर हमेशा नहीं रहेगा। उनकी यह लग्न युवा खिलाड़ियों के लिए एक नया मानक स्थापित करती है। कई क्रिकेटरों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपने करियर को बेहतर बनाया है। वहीं रायुडू ने कहा कि 2027 एकदिवसीय विश्वकप को देखते हुए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल को लगातार अवसर दिये जाने चाहिये। उन्होंने भरोस जताया कि है कि रोहित 2027 विश्व कप की योजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा रहेंगे। रायुडू ने कहा कि उनका अनुभव टीम के लिए अमूल्य है और वे न केवल मैदान पर, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी टीम का माहौल सकारात्मक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि बड़े मैचों में रोहित हमेशा ही असाधारण प्रदर्शन करते हैं। तकनीकी और शारीरिक रूप से वे पूरी तरह सक्षम हैं, और सही समय पर मानसिक रूप से खुद को तैयार करना उन्हें बखूबी आता है। रायुडू ने युवा यशस्वी जायसवाल को भी भारत की भविष्य की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और यशस्वी दोनों ही टीम में जगह बनाने में सक्षम हैं, लेकिन विश्व कप जैसे बड़े टूनार्मेंट को ध्यान में रखते हुए, यशस्वी को तीसरे ओपनर के तौर पर तैयार किया जाना चाहिए।

क्रोएशियन टीम डरने वाली नहीं, रोनाल्डो की पुर्तगाली टीम को कप्तान लुका मॉड्रिच की चेतावनी

न्यूयॉर्क। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-32 में दो जुलाई को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगवाई वाली पुर्तगाल और लुका मॉड्रिच की क्रोएशिया के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा।

इस महामुकाबले से पहले क्रोएशियाई कप्तान लुका मॉड्रिच ने साफ संदेश देते हुए कहा कि उनकी टीम किसी से डरने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पुर्तगाल भी क्रोएशिया का सामना करने को लेकर सहज महसूस नहीं करेगा। क्रोएशियाई टीम के कप्तान लुका मॉड्रिच ने कहा कि उनकी टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। मॉड्रिच ने कहा, पुर्तगाल एक शानदार और बेहद मजबूत टीम है। हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारा अगला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमें सामने देखकर वे भी सहज महसूस नहीं करेंगे।

नेमार ने दिखाई दरियादिली, वेनेजुएला के भूकंप पीड़ितों को दिए 2.1 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने मैदान के बाहर भी बड़ा दिल दिखाते हुए भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए 2.5 लाख अमरीकी डालर (करीब 2.1 करोड़ रुपए) दान किए हैं। यह राशि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जिससे प्रभावित लोगों को भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और रहने की जगह भी उपलब्ध कराया जाएगा। नेमार ने इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि उनकी यह छोटी-सी मदद प्रभावित परिवारों को राहत और हौसला देगी।

कारोबार

व्हाट्सऐप पर किसने किया ब्लॉक, नहीं चलेगा पता

नई दिल्ली। व्हाट्सऐप अपने यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। व्हाट्सऐप पर अब पता नहीं लगाया जा सकेगा की आपको ब्लॉक किया गया है या नहीं। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग फेज में है और अभी आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ टेक एक्सपर्ट्स ने एक ऐसे तरीके का पता लगाया था, जिसकी मदद से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी कॉन्टैक्ट ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं। अब व्हाट्सऐप इस तरीके को बंद करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने सिस्टम में बदलाव की टेस्टिंग कर रही है, ताकि ब्लॉक करने वाले व्यक्ति की प्राइवेसी और बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सके। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सऐप अपने एन्स्क्रिप्शन सिस्टम में बदलाव कर रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी यूजर या रिसर्चर तकनीकी तरीकों से यह पता न लगा सके कि उसे किसी ने ब्लॉक किया है या नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल यह सिर्फ टेस्टिंग में है और व्हाट्सऐप ने इसे सभी यूजर्स के लिए जारी नहीं किया है। यूजर्स के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं बदलेगा। चैटिंग, कॉलिंग, स्टेटस और दूसरे फीचर्स पहले की तरह काम करते रहेंगे।

पेट्रोल-डीजल को लेकर आई गुड न्यूज

केंद्र सरकार ने लिया ये राहत वाला फैसला, 1 जुलाई से होगा लागू

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ी राहत दी है. दरअसल, भारत सरकार ने 1 जुलाई से कमर्शियल खरीदारों के लिए पेट्रोल और डीजल की रिटेल बिक्री पर लगी पाबंदियां हटाने का एलान किया है.

बता दें कि सरकार ने ये पाबंदियां मध्य पूर्व में हुई जंग के बीच ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में रुकावट के दौरान घरेलू तेल सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए आपातकालीन उपायों के तौर पर लगाई थी. दरअसल, सरकार के इस फैसले से 1 जुलाई से व्यावसायिक खरीदार जैसे बस/ट्रक मालिक भी सीधे पेट्रोल पंपों से खुदरा दरों पर तेल की खरीदारी कर सकेंगे. जिससे उनकी लागत कम हो जाएगी.

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच तय की थी 200 लीटर की सीमा

बता दें कि केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इसी महीने व्यावसायिक उपयोग यानी कमर्शियल यूजर्स को रिटेल आउटलेट्स से तेल खरीदने पर रोक लगा दी थी. हालांकि सरकार ने डीजल की बिक्री को ऐसे उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन 200 लीटर तक सीमित कर दिया था. सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया था क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ईंधन सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा था. जिससे स्थानीय स्तर पर तेल की कमी की चिंता बढ़ गई थी. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इसी महीने की शुरूआत में लागू की गई इन पाबंदियों का मकसद पेट्रोल और डीजल की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना, फ्यूल के गलत इस्तेमाल और जमाखोरी को रोकना था. जिससे सही कीमतों पर बिना रुकावट फ्यूल सप्लाई होती रहे.

इसके साथ ही जून का सरकारी आदेश रिटेल फ्यूल और बल्क सप्लाई के बीच कीमतों में बढ़ते अंतर के कारण भी लिया गया था. दरअसल, ट्रेकिंग कंपनियों समेत कमर्शियल कंज्यूमर सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से चलाए जा रहे रिटेल आउटलेट्स से फ्यूल की खरीदारी करने लगे थे. जिसके पीछे की वजह वहां डीजल बल्क सप्लाई पॉइंट्स की तुलना में काफी सस्ता था. बता दें कि भारत में देश की फ्यूल मांग का डीजल 40 फीसदी हिस्सा है. इंडस्ट्रियल यूजर्स को रिटेल कीमतों से लगभग 40 रुपये प्रति लीटर ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था. इससे कीमतों में अंतर हो गया था. जिसके चलते देश के कई हिस्सों में फ्यूल स्टेशनों पर सप्लाई का दबाव बढ़ गया था.

मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने के बाद लिया फैसला

बता दें कि केंद्र सरकार मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य और तेल की सप्लाई चालू होने के बाद कमर्शियल तेल की खरीद पर लगी पाबंदियों को हटा लिया है. इस पाबंदी के हटने से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और इंडस्ट्रियल यूजर्स जैसे कमर्शियल कंज्यूमर को बिना किसी मात्रा की सीमा के रिटेल आउटलेट्स से दोबारा से तेल खरीदने की छूट मिल जाएगी.

जानिए पाबंदियां हटने से क्या कुछ बदलेगा?

बता दें कि सरकार की ओर से लगाई गई ये पाबंदियां हटने से रिटेल मांग में अचानक बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर सरकारी रिटेलर्स पर देखने को मिलेगा. इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन शामिल हैं. ये तीनों मिलकर भारत के एक लाख से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों में से लगभग 90 प्रतिशत का संचालन करते हैं. इस दौरान, प्राइवेट रिटेलर्स यानी जो मार्केट रेट के करीब फ्यूल की कीमत रखते थे की डीजल बिक्री में भारी गिरावट आई, जबकि सरकारी आउटलेट्स पर बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई. बता दें कि सरकार ने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नेट एक्सपोर्टर पर ये अस्थायी पाबंदियां इसलिए लगाई थीं ताकि देशभर में फ्यूल की बिना रुकावट उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. जिसके कारण जियोपॉलिटिकल तनाव ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में खलल था.

भारत बनेगा ट्रांसशिपमेंट हब: अदाणी पोर्ट में 1.4 अरब डॉलर का विदेशी निवेश

अहमदाबाद। अदाणी पोर्ट्स ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने एमएससी ग्रुप के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एमएससी की कंटेनर टर्मिनल संचालन और निवेश कंपनी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (टीआईएल), अदाणी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एवीपीपीएल) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए करीब 1.4 अरब डॉलर का निवेश करेगी।

यह समझौता भारत के बंदरगाह क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निजी निवेश माना जा रहा है। इसके साथ ही विझिंजम पोर्ट हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। इस सौदे के तहत टीआईएल विझिंजम पोर्ट में करीब 1.397 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जो विझिंजम पोर्ट के कुल 2.85 अरब डॉलर के मूल्यांकन में उसकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है।

एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा कि विझिंजम पोर्ट बहुत कम समय में एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बनकर उभरा है। उन्होंने कहा, 'सिर्फ 18 महीनों के भीतर विझिंजम पोर्ट ने 20 लाख टीईयू (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) कार्गो हैंडलिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह भारत का पहला बंदरगाह बन गया है।' उन्होंने आगे कहा कि एमएससी के साथ एपीएसईजेड की लंबे समय से चली आ रही साझेदारी अब विझिंजम पोर्ट तक पहुंचने से उन्हें

काफी खुशी है। उनका विश्वास है कि यह सहयोग वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को अधिक कुशल बनाएगा और भारत की प्रमुख विकसित तथा उभरते वैश्विक बाजारों तक पहुंच को और मजबूत करेगा।

कंपनी ने बताया कि यह सौदा नियामकीय मंजूरियों सहित अन्य आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद पूरा होगा। एपीएसईजेड के अनुसार, एमएससी ग्रुप के साथ यह रणनीतिक साझेदारी कई बड़े फायदे लेकर आएगी। इससे अतिरिक्त कार्गो मिलने के कारण बंदरगाह की क्षमता तेजी से बढ़ेगी और तय समय से पहले परिचालन विस्तार संभव होगा। इसके अलावा, बांग्लादेश से आने वाले कार्गो की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जो फिलहाल दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य ट्रांसशिपमेंट हब पर निर्भर है। साथ ही पूर्वी अफ्रीका के व्यापार मार्गों पर कंपनी की मौजूदगी मजबूत होगी और रिले कार्गो की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी।

टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (टीआईएल) दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटिंग कंपनियों में से एक है। यह एमएससी ग्रुप का हिस्सा है और इसके पास पांच महाद्वीपों में 100 से अधिक कंटेनर टर्मिनलों का नेटवर्क है। साथ ही, कंपनी हर साल 7 करोड़ टीईयू से अधिक कार्गो का संचालन करती है। दिसंबर 2024 में शुरू हुआ विझिंजम पोर्ट भारत का पहला डीप-ड्राफ्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसकी मौजूदा क्षमता 16 लाख टीईयू है। कंपनी ने बताया कि बंदरगाह का विस्तार कार्य जारी है, जिसके बाद दिसंबर 2028 तक इसकी क्षमता 3.5 गुना बढ़कर 57 लाख टीईयू हो जाएगी।

महत्वपूर्ण ख़बर

एनसीटीई पाठ्यक्रमों के द्वितीय चरण का सीट आवंटन जारी

■ भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत एनसीटीई (ठउळए) पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण का सीट आवंटन जारी कर दिया गया है। एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब तक 99,597 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें से 78,784 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण में 21,242 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 19,166 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत 18,563 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व प्रथम चरण में 16,856 विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिलाकर अब तक कुल 35,419 विद्यार्थियों को एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीट आवंटित की जा चुकी है।

प्रशासक अपेक्स बैंक ने सहकारिता सप्ताह का किया शुभारंभ

■ भोपाल। प्रशासक श्री महेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन के व्यापक प्रचार प्रसार युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने नई सहकारी समितियां के गठन तथा सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये सात दिवसीय "व्यापी" थीम पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है, इसी कड़ी में प्रथम दिवस अपेक्स बैंक में सहकारी ध्वज का ध्वजारोहण एवं पौध-रोपण के बाद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैंक के प्रशासक श्री यादव ने "सहकारिता की शपथ" दिलाई एवं सामूहिक रूप से सहकारी गीत के गायन का आयोजन हुआ।

हरित विकास, निवेश और रोजगार... इसी दिशा में आगे बढ़ रही हमारी सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

देश में ग्रीन एनर्जी का पावर हाउस बन रहा है मध्यप्रदेश

भोपाल। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मध्यप्रदेश ने सोमवार को हरित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के साथ नीमच में 500 मेगावॉट क्षमता वाले नीमच सोलर पार्क तथा 450 मेगावॉट क्षमता वाले शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास तथा नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी उपस्थित थे।

निवेश के लिए विशेष मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। करीब 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतरे। पिछले ढाई वर्षों में वैश्विक कंपनियों का 9 हजार 200 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मध्यप्रदेश की धरती पर उतर रहा है, जिससे 4,200 से अधिक नौकरियां सृजित हो रही हैं। मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य, जहां लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू है। उद्योगों के लिए पर्याप्त जमीन, पानी और बिजली उपलब्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि, औषधीय संपदा और उद्यमशीलता के लिए प्रसिद्ध नीमच अब विनिर्माण, ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का भी केंद्र बनने जा रहा है। आज 1 हजार 481 करोड़ रुपये की लागत से 30 औद्योगिक इकाइयों की सौगात नीमच क्षेत्र को मिल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने 1,553.98 करोड़ रुपये की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं विकास कार्यों का भी भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 550 मेगावॉट क्षमता वाला आगर सोलर पार्क भी निमार्णाधीन है, जिसकी इकाइयों के लिए 2.44 और 2.45 रुपये प्रति यूनिट की दरें प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद मध्यप्रदेश देश के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा तथा स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीमच जिले में करीब 160 करोड़ रुपये की लागत से 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश का हरित विकास हमारा लक्ष्य है। हरित विकास के जरिए प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में निवेश लाने और इसके जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अब स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा से इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन उत्तर-पश्चिमी मध्यप्रदेश के नए औद्योगिक ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित हो रहे हैं। नीमच न केवल मध्यप्रदेश का, बल्कि ग्रीन पॉवर सेक्टर का ग्लोबल कैपिटल बन रहा है। उन्होंने बताया कि यहां देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज बन रहा है। नीमच जिले में कुल 675 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं कार्यशील हैं और लगभग 1 हजार 952 से अधिक मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि नीमच में नए सोलर पार्क का शुभारंभ ऐतिहासिक अवसर है। इससे देश में सबसे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी। नीमच की धरती ने प्रदेश को दो मुख्यमंत्री दिए। नीमच ने अफीम उत्पादन और नेत्रदान अभियान में शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संत कबीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में सूर्य देवता ऊर्जा के स्त्रोत हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत 19 मार्च से 30 जून तक कुंए, बावड़ी, नदी, तालाब और अन्य सभी जल स्त्रोतों के संरक्षण के उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य सरकार ने 3 महीने में 10 हजार करोड़ की राशि खर्च कर प्रदेशभर में 2 लाख से अधिक जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार किया है। जल गंगा संरक्षण अभियान में नीमच ने देश में 10वां और प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने म.प्र. के बोर्ड परीक्षा परिणामों में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले नीमच के विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी की मौजूदगी में आज 2 बड़ी सौर परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। कुल 2080 करोड़ की लागत से नीमच में 500 मेगावॉट और शाजापुर में 450 करोड़ मेगावॉट के सोलर पार्क की सौगात मिली है। साथ ही नीमच में 1553.98 करोड़ की 38 औद्योगिक इकाइयों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी हुआ है। नीमच के नए सोलर पार्क से 2.14 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, जो देश में सबसे सस्ती दर है। प्रदेश में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश सबसे तेज गति से रोजगार देने वाला राज्य है। प्रदेश में फूड पार्क, पीएम मित्र पार्क तैयार किए जा रहे हैं। नीमच में 1200 करोड़ से अधिक लागत का सोलर ग्लास तैयार करने वाले प्लांट का भूमि-पूजन हुआ है। नीमच को बहुत जल्द जावरा-उज्जैन होकर भोपाल राजमार्ग की सौगात मिलने वाली है। मंदसौर से भोपाल तक नया हाई-वे भी बनाया जाएगा। नीमच में गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया घर बन चुका है। बहुत जल्द यहां दो और चीते मुक्त प्राकृतिक आवास में छोड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों से गेहूं का एक-एक दाना खरीदा गया है। किसानों को गेहूं के लिए 2625 रुपए प्रति क्विंटल कीमत का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 104 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीदा है। गेहूं के उत्पादन और खरीदी में मध्यप्रदेश ने पंजाब जैसे राज्य को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली उपलब्ध करा रही है। किसान कल्याण वर्ष में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश के किसानों को शून्य ब्याज दर पर आवश्यक लोन मिल रहा है और इसे चुकाने के लिए भी 31 मार्च की बाध्यता खत्म कर दी गई है। किसान जिस तारीख से लोन लेंगे, उसके अगले 12 माह की अवधि में किसी भी तारीख पर लोन चुकाने की सुविधा मिलेगी। हमारे लिए सीमा पर जवान और खेतों में किसान दोनों का बराबर सम्मान है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को हर माह 1500 रुपए की राशि दी जा रही है। राज्य सरकार ने गरीब-जरूरतमंदों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की शुरूआत की है। राहवीर योजना में भी सड़क हादसों के घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रदेश में श्रीराम गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। राज्य में भव्य सांदीपनि विद्यालय और प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन तैयार किए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक के एक गांव को वृंदावन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। डॉ. भीमराम अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 40 लाख लागत की गोशाला शुरू करने पर राज्य सरकार 10 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीमच में भादवा माता मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में अव्वल रहे नीमच जिले की पंचायतों को जल संचयन कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की विद्युत क्षमता में 30 प्रतिशत हिस्सा क्लीन एनर्जी का है। राज्य ने 12 हजार 18 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। जलूद में 271 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से 60 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया गया। मक्सी में जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड द्वारा 6 गीगावाट क्षमता की अत्याधुनिक सोलर विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है, जो भारत की सबसे बड़ी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक होगी। रीवा का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट देश में उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह मां वाग्देवी (सरस्वती) की भूमि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश में राजाभोज की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार ने अभ्युदय मध्यप्रदेश के घोष वाक्य के साथ विकास का सूरज उदय करने का संकल्प लिया है। आज प्रदेश के नीमच और शाजापुर को नए सोलर प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। दुनिया में सोलर एनर्जी का सबसे कम टैरिफ 2.14 पैसे प्रति यूनिट मध्यप्रदेश में उपलब्ध है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। विश्व में स्विट्जरलैंड के बाद भारत दूसरा देश है, जहां रेलवे का शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। मध्यप्रदेश भारतीय रेलवे को बिजली उपलब्ध करा रहा है। मुरैना में 440 मेगावॉट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय नवाचार है। इससे सूर्यास्त के बाद भी 2.70 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल पा रही है। दूसरी ओर, नीमच में गांधी सागर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जो ताप विद्युत के मुकाबले आधी लागत में बिजली उत्पादन करेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जनकल्याण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, पीएम जन-मन जैसी योजनाओं में समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5960 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका लाभ मध्यप्रदेश को भी मिलेगा।

बच्चों में निवेश बढ़ाने से मध्यप्रदेश की मजबूत होगी नींव: राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों में निवेश बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उन्हें वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से आयोग अपनी अनुशंसाओं में बच्चों के विकास से जुड़े आवश्यक संकेतकों को शामिल करने पर गंभीरता से विचार करेगा। श्री पवैया ने राज्य वित्त आयोग कार्यालय, भोपाल में यूनिसेफ के प्रतिनिधिमंडल के साथ

आयोजित बैठक में बच्चों के समग्र विकास, पोषण और समावेशी आर्थिक विकास को लेकर हुठ बैठक में यह बात कही। बैठक में यूनिसेफ मध्यप्रदेश के प्रमुख श्री विलियम हेनलोन जूनियर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि पंचायतों एवं शहरी निकायों के लिए वित्तीय हस्तांतरण का सूत्र निर्धारित करते समय बच्चों की आवश्यकताओं और उनके विकास से जुड़े संकेतकों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 के आधार पर मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में बौनापन, शारीरिक दुर्बलता, कुपोषण तथा बाल विवाह की स्थिति से अवगत कराते हुए इन संकेतकों को आयोग की अनुशंसाओं में शामिल करने का सुझाव दिया। साथ ही इस विषय में यूनिसेफ द्वारा आयोग को तकनीकी एवं विशेषज्ञ सहयोग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया।

बैठक में अध्यक्ष श्री पवैया ने यूनिसेफ के प्रस्तुतीकरण और सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि इस संवाद से राज्य वित्त आयोग को स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तिकरण को बच्चों के विकास से जोड़कर देखने का नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि बच्चों के हितों को प्राथमिकता देने वाली योजनाओं को स्थानीय स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों का समुचित प्रावधान आवश्यक है और आयोग इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगा। बैठक में राज्य वित्त आयोग के सदस्य श्री के.के. सिंह, सदस्य सचिव श्री वीरेन्द्र कुमार सहित आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे। यूनिसेफ की ओर से सुश्री पूजा सिंह तथा दिल्ली कार्यालय से श्री सोमेन बागची भी बैठक में शामिल हुए।

भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल : केंद्रीय मंत्री

भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आयोजित ह्यडिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लॉन्च कार्यक्रमह्न में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। शुभारंभ की गई प्रमुख पहलों में आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान ऐप, आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (एनएचसीएक्स), यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई), ई-सुश्रुत क्लिनिक, ड्रग रजिस्ट्री, कॉमन कोड्स फॉर इंडिया (सीएलसीआई) तथा भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस (बीएचटीएस) शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि 90 करोड़ से अधिक आभा खाते और 100 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनने के साथ भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है।

उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु 2.0 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों सहित सभी आयु वर्ग के नागरिकों को एक ही मंच पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

मुरैना का सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम युगांतरकारी

देश में सबसे कम दो रुपए 70 पैसे प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हुई

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश नए आयाम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुरैना की सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना युगांतरकारी है। मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों विशेषकर चंबल के निवासियों के लिए यह बधाई देने का विषय भी है। इस परियोजना में मात्र दो रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट की प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हुई है जो देश में अब तक की न्यूनतम दर और इस श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूर्व राष्ट्रीय मानक से भी कम है। परियोजना के विशेषता इसका अभिनव बैटरी मॉडल है जिसमें एक बैटरी का रोजाना 2 बार इस्तेमाल करना संभव होगा। इसके साथ ही नीमच और शाजापुर सौर पार्कों को लोकार्पण इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश की एतिहासिक उपलब्धि है। कार्यक्रम को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल में देश में अपने तरह की अनूठी 440 मेगावॉट मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के पावर परचेज एग्रीमेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह एग्रीमेंट और 2 सौर पार्कों का लोकार्पण नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय घटना है। यह एग्रीमेंट निरंतर

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सूर्य की शक्ति को समझा

केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि सूर्य पहले भी था लेकिन इसका उपयोग पहले नहीं हुआ। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सूर्य की शक्ति को समझा, अन्य लोगों ने नहीं समझा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश डॉ. यादव के नेतृत्व में अपने ही रिकॉर्ड तोड़कर देश में सबसे आगे है। मध्यप्रदेश सभी राज्यों में उन्नत है , नई-नई परियोजनाओं से निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जो हमने सोलर पार्क में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं पीएम सोलर पार्क और सरकारी भवनों पर सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के बारे में आज मैंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से निवेदन किया है। एक साल के अन्दर हम सभी सरकारी बिल्डिंग को सोलाराइज करेंगे।

ऊर्जा उत्पादन बढ़ाते और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के पश्चात इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश की एक नई उपलब्धि है। कार्यक्रम में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग श्री मनु श्रीवास्तव, एमडी म.प्र. ऊर्जा विकास निगम श्री अमित तोमर सहित आज सम्पन्न एग्रीमेंट से जुड़े संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी क्षेत्रों में नई वैज्ञानिक खोजों के कारण नागरिकों को बेहतर लाभ दिलवाने की पहल देश में हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे का 20-25 वर्ष पुराना विवाद समाप्त करवाने में पूरा सहयोग किया। उनके मार्गदर्शन में पार्वती- कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना मंजूर हुई, जिसमें राजस्थान भी लाभान्वित होगा और मध्यप्रदेश के चंबल और मालवा से लेकर 13 जिलों के वृहद क्षेत्र को समृद्धि का लाभ मिलेगा। इसी तरह नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, कोल, हाइड्रो के साथ सोलर एनर्जी के कई प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में मुरैना सोलर ऊर्जा भण्डारण की परियोजना वर्तमान दौर में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाओं को क्रियान्वित करने का ठोस उदाहरण है।

केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी ने कहा कि मध्यप्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का आशीर्वाद मध्यप्रदेश को नंबर वन बनाने में मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि सभी राज्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश की प्रगति सबसे तेज है। नई-नई नवकरणीयऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। इन परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना के विकास तथा आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिली है। केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश भी प्रगति कर रहे हैं लेकिन मध्यप्रदेश की प्रगति सबसे अनूठी है।

मध्यप्रदेश आज देश के अग्रणी अक्षय ऊर्जा निवेश गंतव्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर चुका है। राज्य अब केवल बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा भंडारण के माध्यम से स्वच्छ, विश्वसनीय एवं किफायती विद्युत उपलब्ध कराने की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश ऊर्जा भंडारण आधारित अक्षय ऊर्जा खरीद मॉडल को सक्रिय रूप से अपनाने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। सोमवार को 500 मेगावॉट नीमच एवं 450 मेगावॉट शाजापुर सोलर पार्कों के माध्यम से 950 मेगावॉट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता राष्ट्र को समर्पित की गई है। यह उपलब्धि रीवा सौर परियोजना से प्रारम्भ हुई मध्यप्रदेश की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आगर-शाजापुर-नीमच (एएसएन) सौर परियोजना से भारतीय रेल को स्वच्छ विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जबकि रीवा सौर परियोजना से दिल्ली मेट्रो को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश लगातार अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करते हुए अब देश में नवाचार आधारित अक्षय ऊर्जा मॉडलों का अग्रणी राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीमच सोलर पार्क एवं ग्रीनको परियोजना का किया एरियल सर्वे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नीमच के 500 मेगावाट सोलर पार्क एवं ग्राम खिमला में निमार्णाधीन ग्रीनको पम्प स्टोरेज परियोजना का एरियल सर्वे किया। सर्वे के बाद मुख्यमंत्री को पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की प्रगति, तकनीकी विशेषताओं एवं ऊर्जा उत्पादन क्षमता की विस्तृत जानकारी दी गई।

ग्रीनको ग्रुप द्वारा लगभग 11,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही 1920 मेगावाट क्षमता की गांधीसागर पम्प स्टोरेज परियोजना देश की अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। इस परियोजना की ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,326 मेगावाट प्रति घंटा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसे मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के तहत गांधीसागर के मौजूदा जलाशय तथा खिमला में निर्मित किए जा रहे ऊपरी जलाशय का उपयोग पम्प स्टोरेज तकनीक से बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पानी का पुनः उपयोग होगा तथा वाष्पीकरण से होने वाली न्यूनतम हानि को छोड़कर अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होगी। परियोजना में 240 मेगावाट की 7 तथा 120 मेगावाट की 2 द्वि-दिशात्मक टर्बाइन इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। खिमला परियोजना के निर्माण कार्य में वर्तमान में प्रतिदिन तीन हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके पूर्ण होने पर क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर केन्द्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी, प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, ग्रीनको के सीईओ श्री मौर्या, सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक श्री माधव मारू, अपर मुख्य सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्त्व, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती बाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।